twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | बुधवार, 20 अगस्त, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 273, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

केंद्र भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत: जितिन

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने व्यापार समझौतों, प्रोत्साहन योजनाओं, रसद सुधारों और जमीनी स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भागीदारी को मजबूत करने के प्रयासों को आगे बढ़ाया है। उन?होंने सदन को बताया कि सरकार भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने सदन को बताया कि मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के माध्यम से बाजा पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्य रूप से भारत ने 24 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस बीच भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा जारी है, जिसे वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार की ओर से की गई पहलों से कई क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम हुई है और निर्यात को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने बताया कि पीएलआई योजना के तहत 21 परियोजनाओं ने 54 अलग चिकित्सा उपकरणों का निर्माण शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पीएलआई योजना ने भारत में मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित किया है, जिससे मोबाइल फोन का निर्यात 2014-15 में 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसके अलावा फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र में 2.66 लाख करोड़ रुपये की कुल बिक्री हुई है, जिसमें योजना के शुरूआती तीन वर्ष में प्राप्त 1.70 लाख करोड़ रुपये का निर्यात भी शामिल है।

लैंड फॉर जॉब: आज सुनवाई करेगा कोर्ट

नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस की सुनवाई के दौरान आज इस मामले की आरोपित बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पैसे लेकर जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए उससे जमीन नहीं खरीदी जाती। स्पेशल जज विशाल गोगने आरोप तय करने पर 20 अगस्त को भी सुनवाई करेंगे।

सुदर्शन रेड्डी होंगे उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार

बी. सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे

नई दिल्ली

इंडी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया है। यह ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मंगलवार को गठबंधन के घटक दलों की बैठक के बाद किया गया। रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंग। खरगे ने रेड्डी के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेड्डी देश के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश, गौहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में लंबा और उत्कृष्ट कार्य किया है। उनका कानूनी करियर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए संघर्ष से जुड़ा रहा है। बैठक में कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक), तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), आम आदमी पार्टी (आआपा), शिवसेना (यूबीटी) सहित अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। सभी दलों ने सर्वसम्मति से रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने पर सहमति जताई। खरगे ने कहा कि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक विचारधारात्मक लड़ाई है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होकर मैदान में उतर रहे हैं।

रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों को जीवन भर आत्मसात करते हैं: खरगे

खरगे ने कहा कि रेड्डी का नाम इसलिए तय किया गया क्योंकि वे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों को जीवन भर आत्मसात करते रहे हैं। यह चुनाव दो विचारों की टक्कर है और रेड्डी इन मूल्यों के प्रतीक हैं। उन्होंने खरगे का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने सभी विपक्षी दलों की ओर से देश को एक मजबूत और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध विकल्प दिया है। उल्लेखनीय है कि रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की और 27 दिसंबर 1971 को आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की। 1988 से 1990 तक वे सरकारी वकील रहे और छह महीने केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में भी सेवाएं दीं। उन्हें 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 5 दिसंबर 2005 को गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए।

उन्होंने रेड्डी को संविधान और मौलिक अधिकारों का रक्षक बताते हुए कहा कि वे गरीबों के पक्ष में कई ऐतिहासिक निर्णय दे चुके हैं। जब भी लोकतंत्र और संविधान पर खतरा आता है, विपक्ष एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है और यही एकता इस चुनाव में भी दिखाई दे रही है।

रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था

रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की और 27 दिसंबर 1971 को आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की। 1988 से 1990 तक वे सरकारी वकील रहे और छह महीने केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में भी सेवाएं दीं। उन्हें 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 5 दिसंबर 2005 को गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। उनका पूरा करियर न्याय, संविधान और सामाजिक सरोकारों को समर्पित रहा है।

सुदर्शन रेड्डी की जीत से ओबीसी को फायदा: तेलंगाना सीएम

नई दिल्ली

विपक्षी इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मंगलवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन में सहयोगी टीडीपी और बीआरएस और वाईएसआरसीपी जैसी पार्टियों से सुदर्शन रेड्डी के लिए समर्थन मांगा। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि सुदर्शन रेड्डी की जीत से अन्य पिछड़ा वर्ग को फायदा होगा।

'एनडीए आरक्षण खत्म करना चाहता है'

सीएम रेवंत रेड्डी ने बताया, 'जब कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया था, तब जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की थी। उन्हीं की सिफारिशों पर हमने ओबीसी वर्ग को 42 प्रतिशत आरक्षण दिया और कैबिनेट से चर्चा के बाद उसे विधानसभा में पारित कराया गया, लेकिन वे दो विधेयक आज राष्ट्रपति के पास लंबित हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलने की कोशिश कर रहा है और 42 प्रतिशत आरक्षण रोकने की कोशिश कर रहा है।'

तेलंगाना सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा 'जो ओबीसी वर्ग का समर्थन करना चाहते हैं, वे सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें क्योंकि उन्होंने ओबीसी का आरक्षण 42 प्रतिशत करने के लिए काफी मेहनत की। यही वजह है कि हमने सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीते तो यह ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय होगा। तब हम 42 प्रतिशत आरक्षण लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जबकि सुदर्शन रेड्डी की जीत से हमें 42 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और ओबीसी वर्ग को सुदर्शन रेड्डी की जीत से फायदा मिलेगा।'

सीएम ने इन राजनीतिक पार्टियों के सांसदों से की अपील

रेवंत रेड्डी ने कहा कि 'हमारी कैबिनेट और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना और तेलुगु समुदाय की तरफ से तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), जनसेना, वाईएसआर, बीआरएस और एआईएमआईएम समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से अपील करते हैं कि वे एकजुट होकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को जीत दिलाएं। पीवी नरसिम्हा राव के बाद से तेलंगाना को अभी तक ये अवसर नहीं मिला है।' सीएम ने कहा 'सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं, वह सांविधानिक और कानूनी विशेषज्ञ हैं।

हरित हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनना है भारत का लक्ष्य: श्रीपद

नई दिल्ली। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद येसो नाइक ने मंगलवार को कहा कि भारत का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनना है। उन्होंने कहा कि 2030 तक दुनियाभर की मांग का लगभग 10 फीसदी निर्यात करना भी है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने यहां के फिक्की फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग में आयोजित फिक्की ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम भारत को

न केवल एक प्रमुख उत्पादक बनाना चाहते हैं, बल्कि हरित हाइड्रोजन निर्यात का एक वैश्विक केंद्र भी बनाना चाहते हैं। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीपद नाइक ने बताया कि भारत ने अपने महत्वाकांक्षी हरित हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्यों की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 19 कंपनियों को 862,000 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य वैश्विक हरित हाइड्रोजन की लगभग 10 फीसदी मांग को पूरा करना है, जिसके 2030 तक 100 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है। सरकार ने 15 कंपनियों को 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता प्रदान की है, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास को

सहकारिता नीति-2025 का उद्देश्य 10 वर्षों में 16 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करना: शाह

नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 का उद्देश्य अगले दस वर्षों में 16 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिन्हें छह रणनीतिक स्तंभों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। शाह ने कहा कि देश के सहकारी क्षेत्र को नया दृष्टिकोण और गतिशीलता प्रदान करने के लिए इस साल 24 जुलाई को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 लॉन्च की गई है।

यह नीति सहकारी क्षेत्र के समग्र, संतुलित और व्यवस्थित विकास के लिए एक व्यापक खाका प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। यह नीति अगले 10 वर्षों में 16 प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिन्हें छह प्रमुख रणनीतिक स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल सहकारी संस्थाओं की सुदृढ़ता सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाना भी है।

छह रणनीतिक मिशन स्तंभ-नींव को सशक्त बनाना – सहकारी संस्थाओं के लिए अनुकूल कानूनी व नियामकीय ढांचा बनाना, पारदर्शिता, स्वायत्तता और व्यवसाय करने में सुगमता सुनिश्चित करना।

संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ खान एवं खनिज संशोधन विधेयक

नई दिल्ली

राज्यसभा ने मंगलवार को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। यह विधेयक लोकसभा से 12 अगस्त को ही पारित हो चुका है। यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करेगा। विधेयक में प्रावधान है कि पट्टाधारक मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। विधेयक पारित करने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को 11 बजे तक स्थगित कर दी गयी।

सदन की कार्यवाही दोबारा दोपहर दो बजे शुरू होते ही पीठासीन सभापति घनश्याम तिवाड़ी ने केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा के लिए नाम पुकारा। इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सदन में केवल विधायी कार्य ही होने चाहिए। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इस बीच खान मंत्री रेड्डी ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पर बहस शुरू की।

इस विधेयक पर भाजपा सदस्य मयंक कुमार नायक (गुजरात), दीपक प्रकाश (झारखंड) और सीमा द्विवेदी (उत्तर प्रदेश) तथा राकांपा सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने विधेयक के पक्ष में अपनी बात रखी।

नेशनल हेराल्ड केस : कोर्ट ने ईडी के वकील से मांगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने को लेकर ईडी के वकील से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करते हुए ईडी से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।कोर्ट ने 18 अगस्त को ईडी के सहायक निदेशक शिव कुमार गुप्ता की मौजूदगी में दस्तावेजों का परीक्षण किया था।

इसके पहले 7 अगस्त को कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इस मामले से क्या लेना-देना है। कोर्ट ने 14 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गयी। ईडी ने कहा कि जिन लोगों ने दान दिया उनमें से कुछ को टिकट दिए गए। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने इस मामले में गवाहों के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि कांग्रेस को जिन लोगों ने दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गयी। कुछ दानदाताओं को टिकट भी दिए गए। राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।

रील नहीं, रियल उपलब्धियों से लिखा छात्रसंघ का कार्यकाल: अभाविप

नई दिल्ली

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के नेतृत्व दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) ने मंगलवार को कहा कि रील नहीं, रियल उपलब्धियों से हमने लिखा छात्रसंघ का अपना कार्यकाल। डूसू कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में डूसू की सचिव मित्रविंदा कर्णवाल, उपाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल एवं प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने अपने कार्यकाल का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। डूसू पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अभाविप के नेतृत्व वाले छात्रसंघ ने अपने कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बड़े फैसले लेने पर बाध्य किया। आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को प्रभावी बनवाना, "एक कोर्स-एक शुल्क" की नीति पर दबाव बनाना तथा फीस वृद्धि का विरोध कर छात्रों को राहत दिलाना जैसी प्रमुख उपलब्धियां शामिल हैं।

पहली बार पूर्णत: अपशिष्ट मुक्त रही अमरनाथ यात्रा

नई दिल्ली

जम्मू कश्मीर में इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा सफाई, प्लास्टिक-मुक्त व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक रही। इस बार यात्रा में करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के पवित्र गुफा मंदिर के दर्शन किए। इस यात्रा को पहली बार पूरी तरह से पूर्णत: अपशिष्ट रहित (जीरो वेस्ट) बनाया गया। स्थानीय प्रशासन ने यात्रा को गंदगी रहित बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन किया । यात्रा के दौरान हर दिन करीब 11.67 मीट्रिक टन कचरा पैदा हुआ, लेकिन सारे कचरे का शत प्रतिशत निस्तारण किया गया। गीला कचरा खाद बनाने के लिए भेजा गया

और सूखा कचरा रिसाइक्लिंग यूनिट तक पहुंचाया गया। प्रशासन ने 1,016 जगह कूड़ेदान लगाए। हरे रंग के डिब्बे, गीले और नीले, सूखे कचरे के लिए। 65 गाड़ियों ने नियमित रूप से कचरा उठाया। सफाई के लिए 1300 से ज्यादा सफाईकर्मी दिन-रात तैनात रहे। प्लास्टिक पर भी सख्त रोक लगाई गई। एकल-उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पूरी तरह बंद कर दिया गया। लंगर वालों ने भी इसका इस्तेमाल बंद किया। यात्रियों को 15,000 से ज्यादा जूट और कपड़े के थैले बांटे गए।

"प्लास्टिक लाओ, थैला ले जाओ" और "बिन इट, विन इट" जैसे कार्यक्रमों से लोगों को प्लास्टिक के नुकसान और सही तरीके से कचरा फेंकने के बारे में जानकारी दी गई। पूरे यात्रा मार्ग पर 1600 से ज्यादा मोबाइल शौचालय लगाए गए, जिनकी सफाई हर दिन दो बार की गई। हर शौचालय पर क्यूआर कोड लगा था जिससे यात्री तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। करीब 20 हजार यात्रियों ने फीडबैक दिया, जिससे सेवाओं को बेहतर करने में मदद मिली। गंदे पानी और मल को उठाने के लिए 39 डी-स्लजिंग वाहन लगाए गए और सारा मल प्रोसेस किया गया। ग्रीन प्लेज अभियान में 70 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और सफाई की शपथ ली। सेल्फी बूथ, प्रतिज्ञा दीवारें और स्वच्छता किट ने लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। जिम्मेदार यात्रियों को सम्मानित भी किया गया।

शरद पवार बोले- 1978 में वसंतदादा सरकार गिराई, फिर भी 10 साल बाद सीएम पद के लिए मेरा नाम आगे बढ़ाया

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि उन्होंने 1978 में वसंतदादा पाटिल के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को गिराने की पहल की थी। इसके बावजूद उन्होंने एक दशक बाद मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया। शरद पवार ने शनिवार को पुणे में एक कार्यक्रम में कहा कि उस समय कांग्रेस के पास इस तरह का उदार हृदय वाला नेतृत्व था।

शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) बनाई। जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार के तत्कालीन शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी दोफाड़ हो गई।

पुरानी यादों में खोए शरद पवारः 84 साल के राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने याद किया कि आपातकाल के बाद यह भव्य पुरानी पार्टी कांग्रेस (इंदिरा) और स्वर्ण सिंह कांग्रेस में विभाजित हो गई। उस समय वह अपने गुरु यशवंतराव चव्हाण के साथ स्वर्ण सिंह कांग्रेस में ही रहे, लेकिन बाद में हुए चुनावों में किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला।

प्रमुख विरोधियों में से एक था, इसलिए सरकार गिराई

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, आखिरकार हम एकजुट हुए और वसंतदादा को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि, हममें से कई युवा कार्यकर्ताओं में कांग्रेस (आई) के प्रति नाराजगी थी, क्योंकि हम चव्हाण साहब के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए एक दूरी थी। दादा ने इसे पाटने की कोशिश की, लेकिन हमने इसका विरोध किया। उन्होंने याद करते हुए कहा, मैं प्रमुख विरोधियों में से एक था। इस वजह से हमने सरकार गिराने का फैसला किया और हमने ऐसा किया। मैं मुख्यमंत्री बना।

कांग्रेस में ऐसा ही उदार नेतृत्व था

शरद पवार ने कहा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 10 साल बाद हम सब फिर से एकजुट हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि जब अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लेने के लिए बैठक बुलाई गई तो कई नामों पर चर्चा हुई - रामराव आदिक, शिवाजीराव निलंगेकर। पवार ने कहा, लेकिन दादा ने कहा कि अब और चर्चा नहीं। हमें पार्टी का पुनर्निर्माण करना है। शरद इसका नेतृत्व करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कल्पना कीजिए कि जिस नेता की सरकार मैंने गिराई, उसने सब कुछ दरकिनार कर दिया और विचारधारा के लिए एकता को चुना। कांग्रेस में ऐसा ही उदार नेतृत्व था।

धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में होगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन

एजेंसी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 19 अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित मानसून सत्र में पेश होने वाले विधेयक व अध्यादेश के प्रस्ताव रखे गए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2025 विधेयक लाया जाएगा। अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को मिलता था। प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत अब अन्य अल्पसंख्यक समुदायों जैसे - सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी को भी यह सुविधा मिलेगी। यह देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है। साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

1 - प्राधिकरण का गठन - राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्रदान करेगा।

2 - अनिवार्य मान्यता - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी समुदाय द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा पाने के लिए प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3 - संस्थागत अधिकारों की सुरक्षा - अधिनियम अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता बनी रहे।

4 - अनिवार्य शर्तें - मान्यता प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संस्थान का सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है। भूमि, बैंक खाते एवं अन्य संपत्तियां संस्थान के नाम पर होनी चाहिए। वित्तीय गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी या धार्मिक एवं सामाजिक सद्भावना के विरुद्ध गतिविधियों की स्थिति में मान्यता वापस ली जा सकती है।

5 - निगरानी एवं परीक्षा - प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार दी जाए और विद्यार्थियों का मूल्यांकन निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो।

बेंगलुरु में चार मंजिला इमारत में आग लगने से पांच लोगों की मौत

एजेंसी

बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में केआर मार्केट के पास नागरथपेटे में एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। इमारत में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने और इमारत में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। इस हादसे के मृतकों की पहचान मूल रूप से राजस्थान रहने वाले मदन (38), उनकी पत्नी संगीता (33), मितेश (8) और विहान (5) के रूप में हुई है। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे, जबकि सुरेश, जो कि दूसरी मंजिल पर काम करते थे, उनकी भी इस त्रासदी में मौत हो गयी है। पुलिस के अनुसार इमारत के भूतल पर प्लास्टिक मैट के गोदाम में लगी आग तेज़ी से फैल गई। देखते ही देखते आग इमारत की तीसरी मंजिल तक पहुंच गयी और वहां रहने वाले राजस्थान निवासी मदन कुमार, उनकी पत्नी संगीता और बच्चे विहान व नितेश आग में फंस गए। आग में जलने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पहली मंजिल पर काम कर रहे मजदूर सुरेश की भी मौत हो गई है। बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। उन्होंने अभी भी इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका व्यक्त की है।

दही हांडी उत्सव में अलग-अलग हादसों में दो की मौत, 200 से अधिक घायल

मुंबई। देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मथुरा और वृंदावन से लेकर देश के कोने-कोने में मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया, और रात 12 बजे श्रीकृष्ण की भव्य आरती के साथ उनका जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि, महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर हुए दही हांडी उत्सव के दौरान अलग-अलग हादसों में बड़ी दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक घायल हो गए। महाराष्ट्र के मानखुर्द एक व्यक्ति की दही हांडी बांधते हुए मौत हो गई, जिसकी पहचान जगमोहन शिवकिरण चौधरी के रूप में हुई है। वह दही हांडी बांधते समय पहली मंजिल से गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। उन्हें तुरंत शताब्दी गोवंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। बीएमसी और सरकारी अस्पतालों से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार रात 12:30 बजे तक 210 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना मिली, जिनमें से 68 का इलाज चल रहा है और 142 को डिस्चार्ज कर दिया गया। सेंट्रल मुंबई के अस्पतालों में 91 घायल दर्ज किए गए, जिनमें से 60 का इलाज जारी है और 31 को छुट्टी दे दी गई। अस्पतालों से मिली जानकारी के अनुसार, घायल लोगों का डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। संभवत रविवार-सोमवार तक सभी गोविंदाओं को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन पर कार्रवाई, दर्जनों मशीनें जब्त, माफियाओं में हड़कंप

साहिबगंज। झारखंड के साहिबगंज जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रशासन ने मंडरो अंचल के मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत भुतहा मौजा में छापेमारी की। इस दौरान अवैध खदान से खनन में प्रयुक्त दर्जनों मशीनों को जप्त किया गया। टास्क फोर्स की टीम की इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। साहिबगंज सदर एसडीओ अमर जॉन आईद ने इस अभियान का नेतृत्व किया। खनन टास्क फोर्स की टीम के साथ अचानक की गई इस छापेमारी में देखा गया कि स्टार इंडिया खदान के पास बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा था। जैसे ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, वहां खनन में लगी कई गाड़ियां फरार हो गईं। हालांकि, मौके पर मौजूद दर्जनों वाहन और मशीनें जब्त कर ली गईं। एसडीओ अमर जॉन आईद ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि इस इलाके में अवैध खनन हो रहा है। सत्यापन के लिए छापेमारी की गई और मौके पर भारी मात्रा में अवैध खनन पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि जांच में जुटी टीम फरार खननकर्ताओं और वाहनों की पहचान करने में जुट गई है।

लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं शुद्ध मतदाता सूचियां : चुनाव आयोग

एजेंसी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि शुद्ध मतदाता सूचियां लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं। मतदाता सूची तैयार करने के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों की भागीदारी और मतदाताओं एवं राजनीतिक दलों को त्रुटियों को सुधारने के लिए उचित समय और अवसर दिया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि देश में संसद और विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रणाली कानून द्वारा परिकल्पित एक बहुस्तरीय विकेंद्रीकृत संरचना है। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (आईआरओ), जो एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) की सहायता से मतदाता सूची (आईआर) तैयार करते हैं और उसे अंतिम रूप देते हैं। ईआरओ और बीएलओ मतदाता सूची की शुद्धता की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा

कि मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद उसकी डिजिटल और फिजिकल कॉपियां सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं और सभी के देखने के लिए ईसीआई वेबसाइट पर डाल दी जाती हैं। मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए मतदाताओं और राजनीतिक दलों के पास पूरे एक महीने का समय उपलब्ध होता है। चुनाव आयोग ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद डिजिटल और फिजिकल कॉपियां फिर से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं और ईसीआई वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अपील की दो-स्तरीय प्रक्रिया उपलब्ध होती है, जिसमें पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के पास और दूसरी अपील प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ईसीओ के पास की जा सकती है। कानून, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने की पहचान अत्यधिक पारदर्शिता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) ने उचित समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की। उन्होंने एसडीएम, ईआरओएस, डीईओ या सीईओ को कोई त्रुटियां नहीं बताईं। हाल ही में, कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति पूर्व में तैयार की गई मतदाता सूचियों सहित मतदाता सूचियों में त्रुटियों के बारे में मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूचियों के साथ किसी भी मुद्दे को उठाने का उपयुक्त समय उस चरण के दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान होता, जो कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के साथ मतदाता सूचियों को साझा करने के पीछे का उद्देश्य है। अगर ये मुद्दे सही समय पर सही माध्यमों से उठाए गए होते तो इससे संबंधित एसडीएम या ईआरओ को उन चुनावों से पहले गलतियों को, यदि वास्तविक थीं, ठीक करने में सक्षम बनाया जा सकता था। ईसीआई राजनीतिक दलों और किसी भी मतदाता द्वारा मतदाता सूचियों की जांच का स्वागत करता है।

गुवाहाटी में असम-मेघालय के मुख्यमंत्रियों की बैठक, सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर की चर्चा

एजेंसी

गुवाहाटी । असम और मेघालय के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गुवाहाटी में मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज गुवाहाटी में मुख्यमंत्री कॉरनाड संगमा से उत्कृष्ट चर्चा हुई। हमने दोनों राज्यों के परस्पर विकास को सुदृढ़ करने से जुड़े कई मुद्दों पर विचार किया। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन मुद्दों पर

विस्तार से बातचीत हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों की इससे पहले 2 जून को मुलाकात हुई थी, जिसमें 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 पर सहमति बनी थी। इनमें से 5 क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस तक सीमा स्तंभ (बॉर्डर पिलर) लगाने का निर्णय लिया गया था, जबकि पिलिंगाटा क्षेत्र में मतभेद बने रहने के कारण चर्चा जिला उपायुक्तों को सौंप दी गई थी।

असम और मेघालय ने मार्च 2022 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 का समाधान निकाला गया। पहले चरण में 36.79 वर्ग किमी क्षेत्र को लेकर समझौता हुआ, जिसमें असम को 18.51 वर्ग किमी और मेघालय को 18.28 वर्ग किमी भूमि का अधिकार मिला। गौरतलब है कि मेघालय का गठन वर्ष 1972 में असम से अलग राज्य के रूप में हुआ था। असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 को मेघालय ने चुनौती दी थी, जिसके बाद 884.9 किमी लंबी सीमा के 12 क्षेत्रों में विवाद खड़ा हुआ। मुख्यमंत्री सरमा ने मई 2021 में पद संभालते ही घोषणा की थी कि पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद का समाधान उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए अगस्त 2021 में तीन क्षेत्रीय समितियां बनाई गईं, जिनकी सिफारिशों पर मार्च 2022 में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

'लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की', अखिलेश यादव बोले- अंतरात्मा की आवाज सुनें

एजेंसी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग को सुधार ही नहीं, आमूलचूल परिवर्तन की अपरिहार्यता है। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ और वोट चोरी जैसे विपक्षी दलों के आरोपों के बीच अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सपा सांसद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज लोकतंत्र को बचाने का ऐतिहासिक दायित्व चुनाव आयोग के कंधों पर है। माना उनके ऊपर कई प्रकार के अवांछित दबाव काम कर रहे हैं, लेकिन वे ये न समझें कि वे अकेले हैं। जब चुनाव आयोग सही रास्ते पर चल निकलेगा तो करोड़ों भारतवासियों का साथ उनका रक्षा कवच बन जाएगा। सत्य के मार्ग पर चलने वालों के साथ जनता और जन विश्वास स्वयं चलने लगता है।÷ सपा मुखिया ने आगे लिखा, ÷चुनाव आयोग का एक सही और साहसिक कदम देश की अनंत पीढ़ियों का भविष्य और कल्याण सुनिश्चित कर सकता है। सबको अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। इससे पहले, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे। शनिवार को लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, समय-समय पर उंगलियां उठी हैं। चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो, यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों। अखिलेश यादव ने कहा, लोगों का इस संस्था पर विश्वास बढ़ाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग चुनाव आयोग के काम करने के तरीके से असंतुष्ट हैं। हाल ही में, इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाई है।

शिवपुरी- ट्रक और ट्रैवलर में आमने-सामने की भिंडत, गुजरात के चार लोगों की मौत

एजेंसी

शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के शिवपुरी- झांसी फोरलेन हाईवे पर सुबह ट्रक और ट्रैवलर की आमने-सामने की भिड़ंत में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा शिवपुरी-झांसी फोरलेन हाईवे जो नेशनल हाईवे-27 के नाम से जाना जाता है वहां पर अमोला घाटी के नजदीक हुआ है। इस हादसे में गुजरात के 20 लोगों का म्यूजिशियन ग्रुप काशी विश्वनाथ में आयोजित शिव कथा कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद लौट रहा था तभी सुबह शिवपुरी जिले के अमोला घाटी के नजदीक इनकी ट्रैवलर बस हादसे का

शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार हादसा नेशनल हाईवे-27 पर सुबह करीब 5.30 बजे हुआ। बताया जाता है कि 20 लोगों का म्यूजिशियन ग्रुप काशी विश्वनाथ में आयोजित शिवकथा कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद लौट रहा था। सभी लोग गुजरात के जाने-माने कथावाचक डॉ. लंकेश बाबू के टीम के थे। डॉ. लंकेश शुक्रवार को ही फ्लाइट से गुजरात रवाना हो गए थे।ग्रुप के सभी सदस्य गुजरात के मेहसाणा और सुरेंद्रनगर के रहने वाले हैं। शनिवार सुबह लौटते वक्त इनकी ट्रैवलर शिवपुरी जिले के सुरवाया से गुजर रही थी। इसी दौरान बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरी लेन में जाकर ट्रक से टक्कर हो गई। सूचना मिलते ही सुरवाया पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। हादसे में सिंगर हार्दिक दवे (40) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, अस्पताल में उपचार के दौरान राजा ठाकुर (28), अंकित ठाकुर 17) और राजपाल सोलंकी (60) ने भी दम तोड़ दिया।

सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने की सीएम योगी से मुलाकात, राजनीतिक गलियारों में लगने लगे कयास

एजेंसी

लखनऊ। सपा की बागी और फिर बीते निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सपा से निकाले जाने के बाद यह सीएम के साथ उनकी पहली औपचारिक मुलाकात है। उनकी इस मुलाकात के बाद राजनीतिक मायने निकाले जाने शुरू हो गए हैं। मालूम हो कि पूजा पाल को बीते दिनों पार्टी से निकाल दिया गया था।

पूजा पाल ने की थी सीएम योगी की तारीफ

कौशांबी जिले की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक पूजा पाल को आखिरकार पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पिछले साल राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की थी। उस समय से अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विधायक और हाईकमान के बीच तल्खियां तो काफी दिन से चली आ रही थीं। लेकिन बृहस्पतिवार को जब विधायक पूजा पाल ने सदन में खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो सपा अध्यक्ष ने निष्कासन पत्र भिजवा दिया।

उमेश पाल हत्याकांड के बाद बदलने लगा था पूजा का रुखः पूजा पाल 2022 के विधानसभा चुनाव में चायल सीट से सपा के टिकट पर विधायक बनी थीं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूजा का रुख बदलने लगा। वह भाजपा के करीब होने लगीं। उनके आचरण और बयानों को लेकर पार्टी में असंतोष बढ़ रहा था।

पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग, सीएम रंगासामी बोले- निर्णय लेने-लागू करने की शक्तियां नहीं

एजेंसी

पुडुचेरी। मुख्यमंत्री एन रंगासामी पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश के पास त्वरित निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की पूर्ण शक्तियां नहीं हैं। सीएम रंगासामी ने सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लिया। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते पुडुचेरी में निर्वाचित सरकार निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि हर बार निर्वाचित सरकार को अपने निर्णयों को लागू करने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेने की

मजबूरी होती है। हम वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन हैं। ऐसी बाधाएं एक निर्वाचित सरकार के कामकाज के लिए एक व्यावहारिक कठिनाई हैं। उन्होंने आगे कहा कि केवल राज्य का दर्जा ही मददगार होगा। उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचित सरकार को पूर्ण शक्तियां मिलें तो पुडुचेरी और भी ऊंचाइयों को छू सकता है। एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे रंगासामी ने कहा कि हम केंद्र को राज्य के दर्जे की मांग स्वीकार करने के लिए राजी कर रहे हैं। सीएम रंगासामी ने राज्य के दर्जे के लिए निरंतर और एकजुट संघर्ष के लिए सभी राजनीतिक दलों, विधायकों और विभिन्न संगठनों का आभार भी व्यक्त किया।

रंगसामी ने कहा कि पुडुचेरी में प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन वर्तमान 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दलित वर्गों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों की आवास आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री 17-18 अगस्त को नेपाल के दौरे पर

एजेंसी

नई दिल्ली। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 17 एवं 18 अगस्त को नेपाल के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। यह यात्रा नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर हो रही है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से और मजबूत हुए हैं। भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत नेपाल के साथ संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता है। बयान में कहा गया कि मिस्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाएगी और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगी।

अलास्का में हुई बैठक पुतिन के लिए सफल रही : रक्षा विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव

नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्ति विषय पर अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक हुई। लगभग तीन घंटे तक चली बैठक में युद्ध समाप्ति पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस बैठक पर रक्षा विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव ने कहा कि यह रूस के लिए सफल रहा। रक्षा विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव ने बातचीत में कहा कि अलास्का में तीन घंटे चली बैठक पूरी दुनिया में चर्चा में है। यह मीटिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए सफल रही, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सफल नहीं कह सकते, जो भारत के लिए अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों रूस-यूक्रेन में सीजफायर होगा या पहले शांति का फॉर्मूला बनेगा। पुतिन का कहना है कि पहले पीस फॉर्मूला बनाओ, उसके बाद मैं सीजफायर करूंगा। यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका की कुछ हद तक मांग थी कि पहले युद्धविराम हो, उसके बाद शांति का फॉर्मूला बनाते हैं। इसमें यूरोप पीछे हटता दिख रहा है। यह मीटिंग दो पहलू को लेकर की गई थी, एक था रूस-अमेरिका के रिश्ते वापस पटरी पर आएं और दूसरा यूक्रेन-रूस में सीजफायर। यह बैठक सकारात्मक होने से भारत पर लगने वाले अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ हट सकते हैं। शांति का फॉर्मूला जेलेंस्की की सहमति पर ही संभव है, वह चाहे अमेरिका के दबाव में हो या रूस के दबाव से संभव हो। यह रूस की एक तरह की जीत है।

जिन्ना और माउंटबेटन के सामने कांग्रेस ने सरेंडर किया : राकेश सिन्हा

नई दिल्ली । पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि उस समय अगर जिन्ना और माउंटबेटन के सामने कांग्रेस ने सरेंडर ना किया होता तो विभाजन नहीं होता। दरअसल, एनसीईआरटी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष मॉड्यूल जारी किया, जिसमें देश के विभाजन के लिए तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। एनसीईआरटी के इस मॉड्यूल पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष का दावा है कि इतिहास में पीछे जाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा; बल्कि, वर्तमान की परिस्थितियों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एनसीईआरटी के विशेष मॉड्यूल पर पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने बातचीत में कहा कि विभाजन में माउंटबेटन की बड़ी भूमिका थी। जिन्ना अलगाववादी नेता के तौर पर उभर कर आए जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने दोनों के सामने सरेंडर किया। पूर्व सांसद के अनुसार, अगर कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति 1909 से जारी नहीं रखती तो शायद विभाजन की नौबत नहीं आती। कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने की जगह उनके साथ गले मिलने का काम किया। इसलिए सही है कि इस विभाजन के लिए तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तारीफ के जवाब में विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि आरएसएस की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के सामाजिक कार्यों में अद्वितीय रही है। उन्होंने दावा किया कि संघ ने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने में न केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, बल्कि क्रांतिकारियों को हर संभव सहायता भी प्रदान की।

आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी में 25वीं मंजिल से गिरा पत्थर, 12 साल की बच्ची का फट गया सिर; लगे 10 टांके

एजेंसी

नई दिल्ली। सेक्टर-119 स्थित आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी में 25वीं मंजिल से पत्थर गिर गया। इससे 12 साल की बच्ची का सिर का फट गया। उसे 10 टांके लगे हैं। बच्ची के दादा की शिकायत पर कोतवाली सेक्टर-113 की पुलिस ने एनबीसीसी के चीफ जनरल मैनेजर आदित्य पालीवाल, प्रोजेक्ट मैनेजर सुशांत, कृष्णा कंस्ट्रक्शन के कपूर, मैनेजर मंसूर अहमद, साइट इंजीनियर देवेंद्र कुमार, एओए अध्यक्ष आदित्य वशिष्ठ, सचिव अजीत सिंह व उपाध्यक्ष गौरव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सोसाइटी निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उनकी पोती अद्विका पाटनी सुबह साढ़े दस बजे ट्यूशन जा रही थी। वह टावर के पिछले गेट से निकल रही थी तभी पत्थर उसके सिर पर गिर गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे मदरलैंड अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे रेफर कर दिया गया। बच्ची के सिर में 10 टांके लगे हैं।

यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग, भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी

एजेंसी

नई दिल्ली। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंग के दो बदमाशों नीरज फरीदपुरिया और भाऊ रिटोलिया का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें साफ लिखा है कि एल्विश यादव के घर पर जो गोली चली, वह उन्होंने चलवाई है। वायरल पोस्ट में लिखा गया है, हां भाई राम राम सारे भाईया ने... आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो हमने नीरज फरीदपुर और भाऊ रितोलिया ने चलवाई है। आज हमने इसको अपना परिचय दिया है। एल्विश ने बेटिंग ऐप का प्रमोशन करके बहुत से घर बर्बाद किए हैं। इसलिए उन्होंने उनके घर पर फायरिंग की है।

पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा,

वार्निंग देता हूं। जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिलेगा, उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। जो भी सट्टेबाज हैं, तैयार रहो। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पोस्ट की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। जांच एजेंसियां इस पोस्ट की सच्चाई जानने और इसे पोस्ट करने वाले लोगों की पहचान करने में जुटी हैं। बता दें कि भाऊ गैंग एक अपराधी गिरोह है जो हरियाणा और पंजाब में फिरौती, धमकी, वसूली और हत्या जैसे मामलों के लिए जाना जाता है। नीरज फरीदपुरिया इस गैंग का मुख्य सदस्य है। वह हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। उस पर हत्या, जबरन वसूली और धमकी देने जैसे कई संगीन केस दर्ज हैं। नीरज पहले जेल में था और उसे 2015 में उम्रकैद की सजा भी हुई थी, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह विदेश भाग गया। अब वह वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा है।

दूसरा आरोपी, भाऊ रिटोलिया, भी इसी गैंग का अहम हिस्सा है। उस पर भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। वह भी फिलहाल विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर धमकी देता है और लोगों से पैसे वसूलने जैसी घटनाओं को अंजाम देता है।

सीबीआई ने 26 साल से फरार हत्या के आरोपित को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 साल से फरार हत्या के आरोपित मोहम्मद दिलशाद को यहां के इंदिरा गांधी अतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। उसे 11 अगस्त को उस समय पकड़ा गया, जब वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए सऊदी अरब से भारत लौट रहा था। गिरफ्तारी के बाद 14 अगस्त को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

सीबीआई के मुताबिक, दिलशाद पर अक्टूबर 1999 में सऊदी अरब के रियाद शहर में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। उस वक्त वह वहां एक मोटर मेकैनिक और सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। हत्या के बाद वह भारत भाग आया था और तब से फरार था। सऊदी अधिकारियों के अनुरोध पर सीबीआई ने अप्रैल 2022 में इस मामले में केस दर्ज किया था। जांच के दौरान पता चला कि दिलशाद ने नई पहचान के साथ फर्जी पासपोर्ट बनवाया और विदेशों की यात्रा करता रहा। वह कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में आता-जाता रहा। सीबीआई ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया और उसके उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित गांव का भी पता लगाया, लेकिन वह लगातार बचता रहा। बाद में तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर सीबीआई को उसके नए पासपोर्ट का सुराग मिला, जिसके बाद दूसरा एलओसी जारी किया गया। इसके बाद 11 अगस्त को जैसे ही वह मदीना से जेद्दा होते हुए दिल्ली पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने बताया कि मामले की जांच अब भी जारी है।

जयशंकर ने कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून का किया स्वागत

एजेंसी

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने यहां कोरिया गणराज्य (आरओके) के नवनियुक्त विदेश मंत्री चो ह्यून का भारत में स्वागत किया। जयशंकर ने चो ह्यून को उनके हालिया पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और कहा कि एक पुराने मित्र का नए सहयोगी के रूप में स्वागत करना एक विशेष अवसर है।

डॉ. जयशंकर ने चो ह्यून की भारत यात्रा को विशेष बताया और कहा कि कोरिया के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस तथा भारत के स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद ही उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच रिश्तों को दी जाने वाली प्राथमिकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और कोरिया गणराज्य के विशेष रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। विदेश मंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कोरियाई राष्ट्रपति के बीच हाल ही में कनाडा के कानानास्किस में हुई बैठक का भी उल्लेख किया, जिसे उन्होंने 'बहुत सकारात्मक' बताया। डॉ. जयशंकर ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए

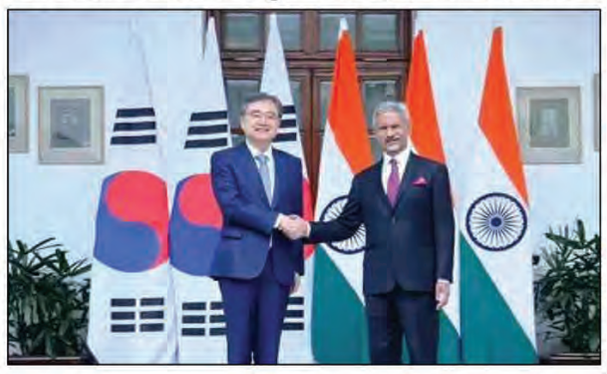

आतंकी हमले की कोरिया द्वारा निंदा किए जाने पर आभार जताया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की सियोल यात्रा के दौरान कोरियाई नेतृत्व से हुई बैठकें काफी सकारात्मक रहीं और स्वयं विदेश मंत्री चो ह्यून द्वारा प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को उन्होंने सराहा भारत और कोरिया के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक सहयोग, संपर्क एवं जन-संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने की इच्छा जताते हुए विदेश मंत्री ने बैठक को सफल बनाने की उम्मीद जताई।

मनीष सिसोदिया के कथित वीडियो को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दी

एजेंसी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कथित वीडियो पर पंजाब में संग्राम छिड़ा है। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी 2027 का पंजाब चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने की साजिश रच रही है। भाजपा ने कथित वीडियो के बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी है।

भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'आप नेता मनीष सिसोदिया का 2027 का चुनाव किसी भी जायज या नाजायज तरीके से जीतने का वीडियो वायरल होने के बाद हमने चुनाव आयोग को यह पत्र लिखा है, ताकि आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव प्रक्रिया को प्रदूषित करने की कोशिशों को रोका जा सके।उन्होंने सवाल उठाते हुए आगे लिखा, जो लोग खुलेआम किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे चुनाव जीतने के लिए पंजाब का माहौल बिगाड़ने या

पंजाब को नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में सुनील जाखड़ ने लिखा, आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, आम आदमी पार्टी साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, सवाल, जवाब, लड़ाई, झगड़ा÷ का सहारा लेगी। उन्होंने आगे लिखा, ÷ऐसे शब्दों की व्याख्या करने पर, आप पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की मंशा स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। पत्र में आगे लिखा, ये बयान भ्रष्ट आचरण अपनाने, मतदाताओं को डराने, दुश्मनी फैलाने और राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के इरादे की खुली स्वीकारोक्ति के समान हैं, जिससे पंजाब की शांति, विकास और समृद्धि को खतरा है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत गंभीर अपराध है। इसके अलावा, ये विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध बयान देने, अवैध रूप से धमकी देने और भय पैदा करने के लिए धारा 196, 197, 353 सहित बीएनएस/आईपीसी के प्रावधानों के भी विपरीत है। सुनील जाखड़ ने चुनाव आयोग से मांग की कि वह इस मामले पर तत्काल संज्ञान ले और जांच कराए। साथ ही, प्राथमिकी दर्ज कराकर मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ सख्त दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए।

कांग्रेस नेता ने की आरएसएस की तालिबान से तुलना, भाजपा ने बताया राष्ट्रवाद और सनातन का अपमान

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता बीके हरीप्रसाद के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तुलना तालिबान से करने के बाद सियासत गरमा गई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला और मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला और कांग्रेस नेता के इस बयान को राष्ट्रवाद और सनातन धर्म का अपमान बताया।

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि कांग्रेस नेता और गांधी परिवार के करीबी बीके हरीप्रसाद कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, वह भाजपा का दुश्मन है। हरीप्रसाद आरएसएस को तालिबान बताते हैं। पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसी भी राष्ट्रवादी संगठन को गालियां देती है, उनका अपमान करती है, और हिंदुओं को बदनाम करती है, जबकि उसे पीएफआई, सिमी और पाकिस्तान

समर्थित आतंकी संगठनों में भाईचारा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सेना में सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइक में खून की दलाली, सिंदूर में तमाशा और राष्ट्रवादी संगठनों में तालिबान दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान में उनको भाईजान नजर आता है। शहजाद ने आगे कहा कि हरीप्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान ने कोई गलत काम नहीं किया है, हम उसके दोस्त हैं, वह भाजपा का दुश्मन है। यह कांग्रेस की मानसिकता और प्रवृत्ति को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सेना, संवैधानिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और सनातन धर्म का अपमान कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। पूनावाला ने सवाल उठाया कि यदि आरएसएस तालिबान है, तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उसके मुख्यालय क्यों गए थे, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने उसकी प्रशंसा क्यों की थी और 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस को क्यों बुलाया गया था? वहीं, भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरीप्रसाद द्वारा आरएसएस की तुलना तालिबान से करना बेहद गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है। इससे साफ झलकता है कि कांग्रेस का तालिबान के प्रति कितना लगाव है। सिरसा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का आतंकियों के प्रति झुकाव कोई नई बात नहीं है। जब-जब आतंकियों का खात्मा होता है, कांग्रेस उनके लिए आंसू बहाती है क्योंकि उसकी राजनीति वोट बैंक पर आधारित है। विशेष वर्ग के वोट पाने के लिए कांग्रेस हमास, आईएसआईएस और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को भी भगवान का रूप देने से नहीं हिचकिचाती।

'पीड़िता के माता-पिता की शिकायतों पर ध्यान दें', राष्ट्रपति भवन का बंगाल के मुख्य सचिव को निर्देश

एजेंसी

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की मृतक डॉक्टर के माता-पिता की ओर से बार-बार की जा रही सुरक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को जांच का निर्देश दिया है। पीड़िता के पिता ने 10, 11 और 12 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तीन ईमेल लिखे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें मानसिक और शारीरिक तकलीफ दी जा रही है और उनकी जान को भी खतरा है। उन्होंने लिखा, हम सब कुछ खो चुके हैं। यह आपके कार्यालय को हमारी तीसरा पत्र है। कृपया जवाब दें।राष्ट्रपति भवन ने 14 अगस्त को यह ईमेल मुख्य सचिव को भेजते हुए कहा, संबंधित ध्यानार्थ एक ईमेल याचिका संलग्न है, जो भारत के राष्ट्रपति को भेजी गई है और स्वयं ही स्पष्ट है। कृपया उनकी मांग पर की गई कार्रवाई

के बारे में याचिकाकर्ता को सीधे सूचित करें। राष्ट्रपति सचिवालय के उप सचिव गौतम कुमार की ओर से भेजे गए ईमेल में यह भी कहा गया, अधिक जानकारी के लिए याचिकाकर्ता से अनुरोध है कि वे सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। डॉक्टर के पिता ने पीटीआई से कहा कि अब उन्हें इस मामले में उचित कार्रवाई की उम्मीद है। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि अब मामले में काम शुरू होगा।

वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग बोला- राजनीतिक दलों ने सही समय पर मतदाता सूची की जांच नहीं की

एजेंसी

नई दिल्ली। विपक्ष द्वारा मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव मशीनरी को त्रुटियां बताने के लिए ''उचित समय'' पर मतदाता सूची की जांच नहीं की। चुनाव अयोग ने इन गड़बड़ियों के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया है।

आयोग ने यह भी कहा कि वह अपने अधिकारियों को खामियों को दूर करने में मदद करने के लिए दस्तावेज की जांच का स्वागत करता है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद दावे और आपत्तियां उठाने का समय, पार्टियों के लिए खामियों को चिह्नित करने का उपयुक्त समय है।बयान में कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) ने उचित समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और यदि कोई त्रुटि थी तो उसे इंगित नहीं किया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि हाल में कुछ राजनीतिक दलों और व्यक्तियों ने मतदाता सूचियों में त्रुटियों के बारे में मुद्दे उठाए थे, जिनमें पूर्व में तैयार की गई मतदाता सूचियां भी शामिल थीं। बयान में कहा गया है कि मतदाता

सूची से संबंधित कोई भी मुद्दा उठाने का उपयुक्त समय 'दावे और आपत्तियां' अवधि के दौरान होता।आयोग ने कहा, यदि ये शिकायतें वास्तव में सही होतीं और इन मुद्दों को सही समय पर और सही माध्यमों से उठाया गया तो संबंधित एसडीएम, ईआरओ को चुनावों से पहले उन्हें सुधारने में सक्षम होते।

आयोग ने कहा, इन त्रुटियों की वजह राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों की तरफ से सूचियां बारीकी से न जांचना है। आयोग के दिशा-निर्देशों के आधार पर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ)-जो एसडीएम स्तर के होते हैं-बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की सहायता से ही सूची तैयार करते हैं और उन्हें अंतिम रूप देते हैं। ईआरओ और बीएलओ इसकी शुद्धता की जिम्मेदारी लेते हैं। मतदाता सूची तैयार करने के प्रत्येक चरण में राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है। बिहार में भी यही देखने को मिला है। आयोग ने फिर दोहराया कि राजनीतिक दलों और किसी भी मतदाता की तरफ से सूची की जांच की जा सकती है। आयोग इसका स्वागत करता है। इससे एसडीएम, ईआरओ को त्रुटियों को दूर करने और मतदाता सूचियों को शुद्ध करने में मदद मिलेगी जो हमेशा से चुनाव आयोग का उद्देश्य रहा है।

युवा कांग्रेस ने शुरू किया घर-घर जाकर मतदाता सूची जांचने का अभियान

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर मतदाता सूचियों में फिर गड़बड़ियों के आरोप को लेकर देशभर में अभियान चलाने की पार्टी की घोषणा के बीच युवा कांग्रेस ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सूची से मिलान करने का अभियान शुरू किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने एक बयान में कहा कि उन्होंने जम्मू (उत्तर) विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ तथाकथित वोट चोरी के खिलाफ घर-घर मतदाताओं से संपर्क कर इस अभियान की शुरुआत की। श्री चिब ने कहा, लोकतंत्र की लड़ाई अब हर बूथ तक पहुँच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर वोट चोरी रोको आंदोलन का एलान किया है। मैंने जम्मू (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र में अपने बूथ की सूचियों से जुड़े मतदाताओं से घर-घर जाकर नामों की पुष्टि शुरू की ।उन्होंने कहा आने वाले दिनों में हर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने बूथ पर धांधली उजागर करेगा।

संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करना राहुल गांधी की आदत : तरुण चुघ

एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लालकिला पर 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से दूरी बनाए जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने इसे संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है और यह उनकी आदत का हिस्सा बन चुका है। बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से दूरी बनाते हैं, दूसरी तरफ 1984 के सिख नरसंहार के मास्टरमाइंड जगदीश टाइटलर को सम्मान देते हैं। चुघ ने इस दौरान एक फोटो के हवाले से कहा कि जगदीश टाइटलर को राहुल गांधी ने 15 अगस्त पर आयोजित कार्यक्रम में बुलाया। जगदीश टाइटलर की फोटो दिखाते हुए चुघ ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए और पंजाब कांग्रेस नेताओं प्रताप सिंह बाजवा और राजा वडिंग की चुप्पी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर नफरत, विभाजन और दंगों की

राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही संविधान की रक्षा का ढोंग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कातिलों का सम्मान करने का सच, यह कांग्रेस का काला इतिहास है।रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कांग्रेस की सरकारों को घोटालों, भ्रष्टाचार और खर्ची-पर्ची के लिए जिम्मेदार ठहराया, विशेष रूप से 2जी घोटाला। उन्होंने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस शासन में 12 लाख करोड़ रुपये की लूट हुई। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस पर गरीबी हटाओ के नारे को खोखला बताते हुए कहा कि इसने गरीबों को और गरीब बनाया, युवाओं को बेरोजगारी और महंगाई दी।

तरुण चुघ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समावेशी विकास के साथ 25 करोड़ गरीबों के जीवन में बदलाव लाई। चुघ ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप ही लगा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों का हित सरकार की नीतियों का मूल आधार है, और नेशन फर्स्ट, किसान फर्स्ट केवल नारा नहीं, बल्कि पीएम मोदी के हर नीतिगत फैसले का आधार है। चुघ ने दावा किया कि मोदी सरकार किसानों की मेहनत, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाले किसी भी कदम को स्वीकार नहीं करेगी। इसके साथ ही, उन्होंने नए भारत की अवधारणा को परिभाषित करते हुए कहा कि यह किसानों को केवल खाद्य सुरक्षा के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि और संप्रभुता के आधार के रूप में देखता है। आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया के पंजाब चुनाव जीतने पर दिए एक बयान पर तरुण चुघ ने कहा कि यह पार्टी साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाकर पंजाब में अशांति फैलाने और चुनाव जीतने के लिए गैरकानूनी और अनैतिक साजिश रच रही है। उन्होंने तिहाड़ जेल रिटर्न्स तिकड़ी का जक्र करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में रह चुके हैं, दिल्ली से आकर पंजाब को लूटना चाहते हैं।

शुभांशु शुक्ला का भारत में लौटने पर भव्य स्वागत; संसद में सफल अंतरिक्ष मिशन पर विशेष चर्चा की योजना

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का रविवार तड़के दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत हुआ। उनके आगमन के बाद लोकसभा में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और शुक्ला के ऐतिहासिक मिशन पर विशेष चर्चा होगी। लोकसभा में होने वाली बहस का विषय है - अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री - विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका।÷ माना जा रहा है कि यह चर्चा संसद में जारी गतिरोध को खत्म कर सकती है और भारत की नई उपलब्धि को सम्मान देगी। शुक्ला जून-जुलाई में दो सप्ताह के अंतरिक्ष मिशन से लौटे। दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह और बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने किया। यह चर्चा विपक्ष द्वारा मतदाता सूचियों में कथित हेराफेरी और चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे को उठाने के प्रयासों के बीच आयोजित की गई है। जून में, शुक्ला आईएसएस के एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने थे - भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद। वह 16 जुलाई को पृथ्वी पर लौटे। यह मिशन केवल भारत ही नहीं, बल्कि पोलैंड और हंगरी के लिए भी चार दशक बाद मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में वापसी का प्रतीक रहा। शुक्ला ने इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) का प्रतिनिधित्व किया और उनका यह अनुभव भविष्य के गगनयान मिशन और भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्ला की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि शुभांशु शुक्ला की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक की अंतरिक्ष यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। यह भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। अंतरिक्ष विभाग ने शुक्ला के मिशन को रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम बताया है और कहा कि यह भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा में गंभीर दावेदारी का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि देश का हर नागरिक अंतरिक्ष क्षेत्र की इस प्रगति से गौरवान्वित है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर गगनयान मिशन और अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

संपादकीय

क्या जनरल असीम मुनीर को पता भी है कि अगर भारत 'स्थगन' की जगह 'पूर्ण विराम' लगा देता है, तो 25 करोड़ पाकिस्तानी 'भूख से मर' जाएंगे? ट्रंप को इसकी जरा भी परवाह नहीं होगी। जनरल मुनीर और राष्ट्रपति ट्रंप पर परमाणु बटन का भरोसा नहीं किया जा सकता। टैम्पा कार्यक्रम में फ्लोरिडा के 120 पाकिस्तानी शामिल हुए। यहां तक कि एक इजराइली रक्षा बल का प्रतिनिधि भी था! एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों कहा था, 'मेरे पास ब्रह्मोस है'। यह नारा पाकिस्तान के 'जिहादी जनरल', फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए था। ट्रंप और मुनीर की दोस्ती इतनी दूर तक नहीं जाती, उनकी जीवन भर की जान-पहचान बिटकॉइन तक ही सीमित है। ट्रंप के बच्चे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप, क्रिप्टोकरेंसी के चक्कर में पागल हो गए हैं और उन्हें जनरल मुनीर की उदार मदद से ट्रंप के खोए हुए अरबों डॉलर वापस दिलाने का काम सौंपा गया है। जनरल मुनीर को ट्रंप ने एक और भूमिका सौंपी है : भारत, भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना को छोटा करना। जनरल मुनीर, सभी पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की तरह, सिर में परमाणु बम लिए हुए हैं, और हर अगले दिन 'हम एक परमाणु राष्ट्र हैं' कहकर साहस जुटाते हैं, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप की पाकिस्तानी रणनीति का पसंदीदा वाक्य है। ट्रंप के पास मुनीर के लिए दूसरी योजनाएं हैं, भारत पर परमाणु हमले से लेकर पाकिस्तान के 'किलो-किलो का परमाणु बम' तक। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भारत और सिंधु जल प्रणाली पर बने भारतीय बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की धमकी दी है। जनरल मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और भारत को झुककर 'सलाम' करना चाहिए। जनरल मुनीर ने 'परमाणु युद्ध' की चेतावनी दी है और यह सब ट्रंप के देश से हो रहा है। जनरल मुनीर का मानना है कि उन्होंने इसमें शामिल सभी लोगों, पाकिस्तान, अमेरिका और भारत, के लिए खतरे बढ़ा दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और जनरल मुनीर सामूहिक विनाश के हथियारों में विश्वास करते हैं, पहला इसलिए क्योंकि उनकी नज? नोबेल शांति पुरस्कार पर है और दूसरा इसलिए क्योंकि सामूहिक विनाश के हथियारों की विनाशकारी प्रकृति है। किसी और जमाने में, अमेरिकी ट्रंप और पाकिस्तानी मुनीर एक-दूसरे के लिए एक 'आइटम', एक 'रिंगर' होते। जनरल मुनीर और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस रहस्य को साझा किया कि युद्धविराम की गुहार किसने लगाई थी? भारत कहता है, 'कैसा युद्धविराम?', बस एक 'समझौता' था। मुद्दा यह है कि मुनीर और ट्रंप की अच्छी बनती है। ट्रंप मुनीर जैसा ही एक और युद्ध चाहते हैं। मुनीर दो महीनों में दो बार अमेरिका जा चुके हैं।वे अमेरिकी जनरलों से मिल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के आदेश पर ही ऐसा हो रहा होगा। पाकिस्तान के वास्तविक शासक जनरल असीम मुनीर ट्रंप जैसे दुस्साहसी हैं कि उन्होंने खुलेआम धमकी दी है कि 'हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे,' जनरल मुनीर ने अमेरिकी धरती से राष्ट्रपति ट्रंप के सामने उनके सुनने के स्थान, ओवल ऑफिस में यह धमकी दी? सभी संकेतों से यही लगता है कि ट्रंप और मुनीर एक-दूसरे के दोस्त हैं। क्या ट्रंप और मुनीर के संबंधों से भारत को चिंतित होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन दोनों बिगड़े हुए लोगों पर चौबीसों घंटे नज? रखनी चाहिए। जनरल मुनीर की यह धमकी कि सिंधु जल प्रणाली पर भारत जो भी बांध बनाने की हिम्मत करेगा, उसे 'मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा', भारत की समझदारी को सीधी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'युद्ध जैसी कार्रवाई' के दावे का क्या हुआ, क्या यह नया सामान्य है? जनरल असीम मुनीर की सख्त बातें संक्रामक नहीं हैं, क्या भारत कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, क्या वह जैसे को तैसा देगा? दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो खून से लथपथ है। जनरल असीम मुनीर भारत की पहचान 'हिंदू' से करते हैं। अब, जल युद्ध छिड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को सिंधु जल पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जनरल मुनीर को चुप कराना और राष्ट्रपति ट्रंप को खेल खेलने से रोकना जरूरी है। क्या जनरल असीम मुनीर को पता भी है कि अगर भारत 'स्थगन' की जगह 'पूर्ण विराम' लगा देता है, तो 25 करोड़ पाकिस्तानी 'भूख से मर' जाएंगे? ट्रंप को इसकी ज?ा भी परवाह नहीं होगी। जनरल मुनीर और राष्ट्रपति ट्रंप पर परमाणु बटन का भरोसा नहीं किया जा सकता। टैम्पा कार्यक्रम में फ्लोरिडा के 120 पाकिस्तानी शामिल हुए। यहां तक कि एक इज?ाइली रक्षा बल का प्रतिनिधि भी था! ट्रंप के लंच में वे क्या कर रहे थे और जब क्रिप्टोकरेंसी की बात हो रही है, तो वे क्या कर रहे हैं? कल्पना कीजिए, दुनिया की सेहत एक सिक्के पर निर्भर है! जनरल असीम मुनीर खुद को और देश-विदेश में बसे पाकिस्तानी प्रवासियों को दिलासा दे रहे हैं। उनकी कुटिल सोच में, पाकिस्तान ने 'चार दिवसीय युद्ध' जीत लिया। 'भारतीयों को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए... खेल भावना एक गुण है,' पाकिस्तानी नेता ने टैम्पा पाकिस्तानियों से कहा। यह प्रधानमंत्री मोदी की गलती है। मोदी को कम से कम उम्मीद होने पर भी बात बीच में ही टाल देने की आदत है। मोदी के पीछे हटने और पीछे हटने की एक पूरी सूची है। दुख की बात है कि कुछ नहीं किया जा सकता। ट्रंप, मुनीर और मोदी की तिकड़ी! मिसाल के तौर पर, मुनीर द्वारा कुरान से उद्धृत इस कथन का क्या मतलब है: 'एक ट्वीट कहता है सूरा फिल, मुकेश अंबानी की तस्वीर के साथ ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि हम अगली बार क्या करेंगे?' सूरा अल-फिल, जिसे 'हाथी' भी कहा जाता है, कुरान का 105वां अध्याय है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अल्लाह ने दुश्मन के युद्ध के हाथियों पर पत्थर गिराने के लिए पक्षियों को भेजा और उन्हें 'चबाया हुआ भूसा' बना दिया, असीम ने टैम्पा को बताया। 'हम भारत के पूर्व से शुरूआत करेंगे, जहां उन्होंने अपने सबसे मूल्यवान संसाधन खोजे हैं, और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे।' सवाल यह है कि क्या 'जिहादी जनरल' मुनीर को पता है कि भारत की पहचान हाथी से है और भारत का पूर्वी भाग भारत के हाथियों का घर है? हाथियों की तो बात ही छोड़िए, जनरल मुनीर ने भारत की तुलना एक चमचमाती मर्सिडीज से और पाकिस्तान की तुलना एक टूटे हुए कूड़ेदान (सेना के) से की और चेतावनी दी कि जब पेंट उखड़ता हुआ यह कूड़ेदान एक जर्जर पाकिस्तानी सड़क पर, जहां स्पीड-ब्रेकर के लिए गड्ढे बने हैं, मर्सिडीज से टकराएगा, तो मर्सिडीज की चमक फीकी पड़ जाएगी!

क्या बुजुर्ग डोनाल्ड ट्रंप उस पाकिस्तानी को जानते भी हैं जिसके साथ उनका रिश्ता है? आखिर मेंमेलानिया ट्रंप की हंसी अंतिम होगी!

देश ही नहीं विदेशों में भी परेशान है लोग आवारा कुत्तो से

अशोक भाटिया

रात में घर लौटना चोरों, लुटेरों या ड्रग एडिक्ट्स का नहीं, बल्कि आवारा और आवारा कुत्तों के उपद्रव का खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन हाल ही में, कुत्तों के इस झुंड ने कई लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। समस्या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसने सुप्रीम कोर्ट को आवारा कुत्तों की समस्या पर अपनी याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया है। इससे समस्या की गंभीरता का पता चलता है। हमारे देश में कुत्ते प्रेमियों की एक महत्वपूर्ण संख्या है। ये कुत्ता प्रेमी अपने घरों में नहीं, बल्कि सड़कों पर इन कुत्तों की देखभाल करना चाहते हैं। हम चौक में आवारा कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं। एक तरफ कुत्तों द्वारा किए गए उपद्रव की जिम्मेदारी नहीं लेने और दूसरी तरफ कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने, सड़कों पर प्रदर्शन करने, अदालत का दरवाजा खटखटाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। रात में, अभिजात वर्ग अपने वाहनों में भोजन के साथ सड़कों पर चलने वाले आवारा कुत्तों की तलाश करता है। जबकि दिल्ली में काटने की संख्या बढ़ रही है, इस साल जनवरी और जून के बीच 65,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया गया है। रात में कचरा इकट्ठा करने वाले, कचरा परिवहन कर्मचारी, धुआं बीनने वाले, धुआं नियंत्रण कार्यकर्ता और जो लोग नगरपालिका न्यायालयों में नागरिक शिकायतों और नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने के लिए काम करते हैं, उन्हें महीने में कई बार कुत्तों के हमलों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल कुत्ते के काटने के 37 मामले होते हैं। एक लाख से अधिक घटनाएं होती हैं; रेबीज से 305 लोग मरते हैं। अकेले नसबंदी पर्याप्त नहीं है, अब मानव जीवन की रक्षा करना आवश्यक है। हालांकि 3।7 मिलियन का आंकड़ा प्रलेखित है, संख्या अधिक होने की संभावना है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक कचरे के डिब्बे आवारा कुत्तों का घर बन गए हैं। संबंधित व्यक्ति न्यायालय में पंजीकरण कराने और प्रशासन को शुल्क का भुगतान करने में आनाकानी कर रहे हैं। अक्सर बचपन से ही कुछ ऐसे तत्व घर में कुत्ते पालते थे, बाद में उन्हीं कुत्तों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कि दिल्ली में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखा जाए, मुंबई में आवारा कुत्तों की सुरक्षा की मांग अब मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली , पनवेल, उरण, नवी मुंबई, बदलापुर, अंबरनाथ, वसई-विरार के मुंबईकरों से शुरू हो गई है। हमलों की समस्या गंभीर हो गई है। जब स्थानीय प्रशासन नसबंदी के लिए कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करता है, तो ये कुत्ता प्रेमी आवारा कुत्तों को छतों पर और सोसायटियों के परिसर में छिपा देते हैं। पिछले 15 वर्षों में,

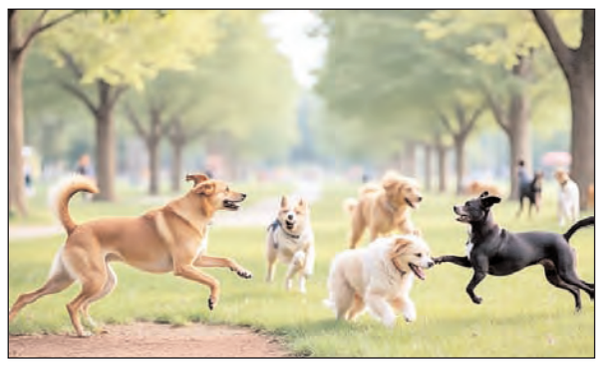

12.73 लाख मुंबईकरों को आवारा कुत्तों ने और 1,35,253 मुंबईकरों ने 2024 में काटा है। आवारा कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें भी आश्रय स्थलों में शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। 2014 की जनगणना के अनुसार, मुंबई में 95,174 आवारा कुत्ते थे। पिछले 11 सालों में मुंबई में आवारा कुत्तों की संख्या कुछ लाख तक पहुंच गई है। पिछले 22 सालों में मुंबई में 16.60 लाख आवारा कुत्तों की समस्या पैदा हुई है। हर साल बीएमसी इन आवारा कुत्तों की नसबंदी करती है। हालांकि, यह मुद्दा हर मानसून में सामने आता है। आवारा कुत्तों की समस्या के नियंत्रण से बाहर होने से पहले उसके समाधान की मांग की जा रही है। मुंबई में कई विधायकों ने न केवल निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि शहर और उपनगरों में भी आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए बीएमसी के साथ ताहो तोड़ दिया है। इसकी मांग की गई है। इसने यह भी दावा किया है कि इससे कुत्तों के हमलों की घटनाओं में कमी आएगी और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बढ़ती चिंता को कम करने में मदद मिलेगी। 2009 और 2024 के बीच, आवारा कुत्तों के नियंत्रण पर 24.03 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। आवारा कुत्तों की समस्या मुंबई के पास नवी मुंबई में भी है। लिया। दीघा, ऐरोली और घनसोली के साथ-साथ मिडक इलाकों और गांव में विभाजन से दहशत अधिक है। रात में नवी मुंबई में आवारा कुत्तों के गिरोह घूमते नजर आते हैं। देर रात घर आने वालों के मन में आवारा कुत्तों का डर बढ़ गया है। हालांकि, इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे प्रशासन के लिए नागरिकों से सहयोग हासिल करना भी उतना ही जरूरी है।

यूरोप के इस देश नीदरलैंड ने एक व्यापक वेलफेयर-फर्स्ट रणनीति अपनाई। पेट स्टोर से पालतू खरीदने पर भारी टैक्स लगाया गया ताकि लोग शेल्टर से गोद लेने को प्रोत्साहित हों। सरकार ने CNVR प्रोग्राम (Collect, Neuter, Vaccinate, Return) शुरू किया, जिसमें आवारा कुत्तों की मुफ्त नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है। कड़े एंटी-क्रुएल्टी कानून और भारी जुमार्ने लागू किए गए। साथ ही रेस्क्यू और कानून लागू करने के लिए समर्पित एनिमल वेलफेयर यूनिट बनाई गई। देशव्यापी गोद लेने के अभियान और पब्लिक अवेयरनेस से जिम्मेदार पेट ओनरशिप को बढ़ावा दिया गया।

मोरक्को में हर साल करीब 1 लाख लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं। 2019 में सरकार ने rap-Neuter-Vaccinate-Release (TNVR) प्रोग्राम शुरू किया। इसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और रेबीज का टीका लगाया जाता है, फिर उन्हें आईडी टैग के साथ उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग जान सकें कि वे सुरक्षित हैं।

मोरक्को के गृह मंत्री ने आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए 100 मिलियन डॉलर का बजट घोषित किया। इसके तहत 130 कम्यूनल हाइजीन ऑफिस खोले गए, जिनमें 60 डॉक्टर, 260 नर्स, 260 हेल्थ टेक्नीशियन और 130 वेटरिनेरियन नियुक्त किए गए, ताकि 1244 नगरपालिकाओं में शेल्टर मैनेज किए जा सकें।हालांकि, देश को एक्टिविस्ट्स और एनिमल राइट्स ग्रुप्स की आलोचना झेलनी पड़ी, जिन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 2030 ऋकऋअ वर्ल्ड कप से पहले गुपचुप तरीके से कुत्तों को मार रही है।

कंबोडिया ने बड़े पैमाने पर डॉग वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया, जिसमें सिर्फ दो हफ्तों में 2।2 लाख कुत्तों को रेबीज के टीके लगाए गए। ये पहल बीमारी फैलने से पहले रोकथाम पर केंद्रित थी, न कि हमले के बाद कार्रवाई पर।

भूटान ने Nationwide Accelerated Dog Population Management and Rabies Control Programme (NADPM & RCP) के तहत 100% फ्री-रोमिंग डॉग पॉपुलेशन की नसबंदी कर दी। World Organisation for Animal Health के श्रोत से मिली जानकारी के अनुसार ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मार्च 2022 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट अक्टूबर 2023 में पूरा हुआ, जिसकी लागत $3।55 मिलियन रही।

तीन चरणों में चले इस अभियान में 12,812 लोग शामिल थे, जिनमें वेटरिनेरियन भी थे। 217 क्लीनिक से ऑपरेशन करते हुए कुल 61,680 कुत्तों की नसबंदी की गई, जिनमें से 91% आवारा थे।

तुर्की में कानून के तहत लाखों आवारा कुत्तों को हटाने, शेल्टर में रखने, टीकाकरण, नसबंदी और गोद लेने के लिए देने का प्रावधान है।

राहुल की तीसरी यात्रा : मोदी जी के लिए बड़ा चैलेंज

शकील अख्तर

गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस में कुछ लोग बहुत बोलते हैं। मगर यह वे हैं जो अपनी सीट भी कभी निकाल नहीं पाते। राहुल गांधी अब कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में हैं। अपनी तीसरी यात्रा शुरू कर दी है। पार्टी में कहीं कोई विरोध तो दूर की बात अब असहमति भी नहीं बची है। यहीं से राहुल को इसका उपयोग करने की जरूरत है। कांग्रेसियों के लिए नहीं। राहुल की तीसरी यात्रा शुरू। आज के कांग्रेसियों को यह अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि उन्हें राहुल जैसा जांबाज नेता मिला। नहीं तो जिस तरह 2011-12 में उन्होंने बिना लड़े अन्ना हजारे जैसे एक नकली आन्दोलनकारी के सामने हथियार डाल दिए थे उसके बाद पार्टी को फिर खड़ा करने की संभावनाएं कम बची थीं। इसीलिए 2014 में आते ही मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने लगे थे। कांग्रेसियों ने भी उसमें सहयोग देते हुए 2019 में राहुल गांधी का अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया था। यह पूरा इतिहास बताना इसलिए जरूरी है कि इस समय मोदी के कमजोर होने के साथ कांग्रेस के जिन नेताओं ने इसमें कुछ नहीं किया उनका अहंकार फिर यूपीए के समय के मुगालतों तक पहुंच गया है। बिहार में राहुल की यात्रा ने कांग्रेसियों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। पिछले हफ्ते कांग्रेस की स्क्रिनिंग कमेटी पटना गई थी। वहां उसने संभावित उम्मीदवारों से मुलाकात की। अभी 13 और 14 अगस्त को। दो हजार प्रत्याशियों के आवेदन आए हैं। कांग्रेस ने हर सीट पर संभावित उम्मीदवारों का पैनल बनाना शुरू कर दिया है। इन सबमें कोई बुराई नहीं है मगर बस यह याद रखना चाहिए कि यात्रा राहुल और तेजस्वी दोनों की है। लेफ्ट के लाल झंडे भी बड़ी संख्या में शामिल हैं और सामाजिक आधार पर बनीं दूसरी पार्टियां भी। लेकिन बड़ी ताकत आरजेडी है। अगर चुनाव जीतेगी तो आरजेडी और हारेगी तो वह। कांग्रेस और लेफ्ट सहयोगियों की भूमिका में ही हैं। मजबूत सहयोगी हैं। अपना अलग जनाधार है मगर लीड आरजेडी ही करेगी। लोकसभा के यूपी के चुनाव में कांग्रेस ने वहां के मुख्य दल सपा के साथ ठीक से मिलकर चुनाव लड़ा तो उसकी 6 सीटें आ गईं। सपा की 37 और भाजपा

जिसने 2019 में 80 में 63 सीटें जीती थीं नंबर दो की पार्टी बनकर 33 पर रूक गई। मोदी जी को ऐसा झटका लगा कि सामान्य बहुमत भी नहीं मिल पाया। 240 पर रुकना पड़ा। गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस में कुछ लोग बहुत बोलते हैं। मगर यह वे हैं जो अपनी सीट भी कभी निकाल नहीं पाते। राहुल गांधी अब कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में हैं। अपनी तीसरी यात्रा शुरू कर दी है। पार्टी में कहीं कोई विरोध तो दूर की बात अब असहमति भी नहीं बची है। यहीं से राहुल को इसका उपयोग करने की जरूरत है। कांग्रेसियों के लिए नहीं। कांग्रेस पार्टी के विचार और नीतियों के लिए। उसके कार्यकताओं के लिए और देश की जनता के लिए। आप यकीन मानिए कि अगर आज की तारीख में जैसा कि मोदी जी चाहते हैं कांग्रेस राहुल विहिन हो जाए तो ये कांग्रेसी 10 टुकड़ों में बंट जाएंगे और इनमें से आधे टुकड़े मोदीजी से जाकर मिल जाएंगे। मोदी जी और भाजपा जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है वह कांग्रेस मुक्त नहीं राहुल मुक्त या नेहरू गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस की कोशिश करती है। तो राहुल इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ फार्म या कह सकते हैं कि अभी तक के राजनीतिक जीवन के सर्वोच्च शिखर पर हैं। पार्टी में भी और विपक्ष में भी। यही वह समय है जब उन्हें असली लक्ष्यों के लिए काम करना शुरू करना चाहिए। पार्टी में लोकतंत्र, उदारता, सख्ती नहीं करना यह सब तब ठीक होता है जब आपकी गाड़ी सही चल रही हो।

इस समय तो गाड़ी को पटरी पर लाने की जरूरत है। उनकी एक के बाद एक कोशिशों ने वास्तव में मोदी जी को बैकफुट पर धकेल दिया है। यह सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर फैसला, चुनाव आयोग की प्रेस कान्फ्रेंस और बिहार की यात्रा में पहले दिन उमड़ी हुई जोशीली भीड़ सब राहुल का प्रभाव बढ़ने का ही नतीजा है। ऐसे में पहला वास्तविक लक्ष्य बिहार जीतना होना चाहिए। इस समय मोदी के कुछ भी अनुकूल नहीं है। बस कांग्रेस और विपक्ष कोई गलती न करे तो मोदी जी के लिए बिहार चुनाव वाटर लू साबित हो सकता है। यह हार गए तो फिर वापसी करना मुश्किल है। उम्र 75 की हो चुकी होगी। जिसे आधार बनाकर उन्होंने संगठन में सबसे मजबूत नेता रहे लालकृष्ण आडवानी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था।

भाजपा में वाजपेयी संगठन के बाहर ज्यादा पहुंच रखते थे। मगर संगठन के अंदर तो सारी ताकत आडवानी के पास थी। उन्हें भी 75 पार के नाम पर सक्रिय राजनीति से हटा दिया गया। तो सोचिए मोदी जी अगर बिहार हार जाते हैं तो फिर 75 के बाद उनका पद पर बना रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। सीज फायर उसके बाद ट्रंप का टैरिफ किसी पर वे एक शब्द नहीं बोल पाए। और अब वोट काटने पर उनकी चुप्पी। लोकतंत्र में एक साथ 65 लाख वोट कटें और सत्ताधारी पार्टी चुप रहे। क्या मतलब है इसका? कि वोट सारे उसके विरोधियों के कटे हैं और क्या मतलब हो सकता है? पार्टी वहीं चुप रहती है जहां उसे फायदा होता है।

एकजुटता के अभाव में गजनवी ने सोलह बार देश को लुटा

अरविंद रावल

इसे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कहा जाए या फिर विडम्बना कही जाए कि अपनी अगाथ आस्था के प्रतीको, अपनी अस्मिता की पवित्रता को बचाने के लिए करोड़ो हिंदुस्तानी अपनी गीता, अपनी रामायण और अपने महादेव के नाम पर मन कर्म और वचन से कभी एकजुट हुए ही नही हे और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि महमूद गजनवी नामक एक लुटेरा एक कुरान के नाम पर अपने कुछ हजार लोगो को एकजुट कर हजारों मील दूर से हमारे देश में आकर सेकड़ो राजघरानो को लांघकर कैसे तीस सालों में 16 बार हमारे देश के उस समय के सबसे विख्यात प्रभास पाटन के समृद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटता रहा है और हम अपनी आपसी फुट बेर भावना के चलते उस लुटेरे के हाथो एक नही दो नही पुरे सोलह बार अपना सबकुछ लुटाते रहे ! गजनी के दोर में भारत की सीमाएं ईरान अफगान बॉर्डर तक लगती थी ! जिस रास्ते गजनवी भारत में घुसा था और सोमनाथ तक पहुंचा था तो इस बीच सेकड़ो राज घराने राजा महाराजाओ को लाँघ कर ही गजनवी हर बार आया गया होगा लेकिन क्या किसी राजा महाराज में भी इतना सामर्थ्य नही था कि उस लुटेरे गजनवी को रोक सके या फिर हमारे अपनों के ही बीच ही मनभेद इतने गहरे थे कि सबकुछ आखो के सामने लुट जाने दिया अपनों तो इसका उत्तर हम भारतीयों को अपने अंदर ही देखने पर मिल जाएगा। बेकोल महादेव को हमने लुटने दिया अपने घरो की अस्मिताओ को लुटेरो के हाथो लुटने दिया लेकिन हमारे जिम्मेदार कल भी सूरा सुन्दरी शराब और सत्ता में डूबे हुए थे और आज भी कमोबेश हम अपने घरो परिवारों समाज में भी में टुकडो में बटकर फिर किसी गजनवी के हाथो लुटाने के लिए बेकरार हे ! महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के पहले भारतीयों की मानसिकता को समझने के लिए अपने गुप्तचरों को सूफी , मौलवी फकीर के भेष में अच्छे से अध्ययन करवाया और उस दोर के राजाओ और सामन्तो की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने अभियान को हर बार सफल बनाया। महमूद गजनवी को पता था कि भारत मे भगवान सोमनाथ के प्रति आस्था विश्वास रखने वाले हजारों राजा लाखो व्यापारी ओर कोटि कोटि भक्त है लेकिन उन भक्तो में अपने भगवान सोमनाथ के प्रति मर मिटने की एकता रखने वाले भक्त मुट्ठी भर भी नही है। महमूद गजनवी को पता था कि हिंदुस्तान के अधिकांश राजा महाराजा व्यापारी ओर उच्च धनिवर्ग के लोगो की आस्था अपने भगवान अपने धर्म के प्रति तो बहुत है किंतु उनमें अपने भगवान अपने धर्म के नाम पर आपसी एकजुटता नही है। हिंदुस्तान के लोगो मे एकजुटता नही होने का सबसे प्रमुख कारण धन लालसा, राज्य भोग, सुरा सुंदरी शबाब ओर अंधविश्वासी होना है। उस समय के हमारे राजाओं ओर दरबारी लोगो की इन्ही कमजोरियों को फायदा उठाकर महमूद ईरान अफगानिस्तान से चलकर भारत की सीमा में आया और यहां के सेकड़ो राजाओं को धनबल से बाहुबल से और सुरा सुंदरियों के बल से खरीदकर सोमनाथ तक बेधड़क चला आया। जिन राजाओं ने गजनवी को रोकने का साहस किया उन्हें उसी की ही जाती के राजाओं के साथ मिलकर मरवा दिया ओर पूरे सोलह बार हिंदुस्तानियों को चिढ़ाता हुआ अपने अभियान को सफल बनाकर चला गया।

आज के संदर्भ में यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज हम भारतीय भी अपने देश अपने धर्म अपने समाज और अपने भगवान के प्रति बहुत अगाथ आस्था रखते है लेकिन विपती के समय क्या कभी हम सभी स्वार्थ लालसा, गीले शिकवे, अपना पराया, जाति धर्म, ऊच नीच, अमीरी गरीबी से परे हटकर एकजुट होकर अपने देश अपने भगवान ओर अपने धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को क्या हमेशा तैयार है ?

यदि इसका उत्तर बिना किसी विचार, शंसय या झिझक के हा है तो कभी भी महमूद गजनवी जैसे लुटेरे तालिबानी आतंकी वह हमारा हमारे हिंदुस्तान ओर हमारी गहरी आस्था के प्रतीक भगवानों का कुछ भी नही बिगाड़ पाएंगे। इसके उलट यदि हम भारतीयों के मन मे थोड़ा भी विचार शंसय या झिझक रहा तो फिर कोई तालिबानी आतंकी महमूद गजनवी की तरह एक कुरान के नाम पर मरने मिटने वाले चंद हजार लोगो के बल पर हम कोटि कोटि भारतीयों को , हमारी आस्था, हमारी अस्मिता ओर हमारे देश को चोट पहुचाने का दुःसाहस कर सकते है।

त्याग के साये में जन्मा अहम

डॉ. सत्यवान सौरभ

घर के आँगन में पीपल का पुराना पेड़ खामोशी से खड़ा था। उसकी छाँव में खेलते हुए बीते साल जैसे किसी पुराने संदूक में बंद पड़े थे। इस घर की दीवारों ने न जाने कितनी कहानियाँ देखी थीं – हँसी की, आँसुओं की, त्याग और उपेक्षा की। बड़े बेटे ने महज छठी कक्षा से ही घर का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। पिता का स्वभाव ऐसा कि घर के कामों में कोई स्थायी हाथ बँटाना उनकी आदत में नहीं था। न कोई बड़ा सपना, न मेहनत से आगे बढ़ने की चाह। उस उम्र में, जब बाकी बच्चे अपनी पढ़ाई और खेलों में मग्न होते हैं, उसने ट्यूशन पढ़ाकर खुद की पढ़ाई भी पूरी की और छोटे भाई की भी।

बहनों की पढ़ाई के लिए जितना संभव हो सका, उसने पैसे जुटाए। कपड़े, किताबें, फीस – हर जरूरत में वह आगे खड़ा था। शादी के बाद उसकी पत्नी भी इस जिम्मेदारी में बराबर की साझेदार बनी। वह न सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी निभाती, बल्कि ननदों को उनके घर जाकर पढ़ाती, उन्हें अपने साथ कोचिंग ले जाती। घर की छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए बड़े की नौकरी और उसकी पत्नी के पैसों पर ही घर चलता रहा। पत्नी के फिक्स्ड डिपॉज़िट तक घर के खर्च में लग गए। जब उसकी पत्नी की भी नौकरी लगी, तब भी उनकी पूरी तनख्वाह घर की उन्नति में लगती रही। कई सालों बाद बड़ा भाई नौकरी में स्थिर हुआ। उसने घर का सपना सजाया – नया मकान बनवाया, एक पुरानी गाड़ी खरीदी ताकि घर के काम आसानी से हों। लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल भी ज्यादातर छोटा ही करता। यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी गर्भवती थी, तब भी छोटा गाड़ी लेकर चला जाता और भाभी बस से ड्यूटी जाती। बड़ा भाई खुद किसी और के साथ काम पर जाता। बड़े के बेटे के जन्म से पहले ही छोटे भाई की नौकरी लग चुकी थी। पर जिम्मेदारियों में हाथ बँटाने या घर का पुराना कर्ज. चुकाने के बजाय वह अपने ही आराम में लगा रहा। एक-दो बार बड़े ने माता-पिता से भी कहा कि छोटे की जरूरतों पर ध्यान दो, पर उसकी इच्छाओं को पंख मत लगाओ। मगर माता-पिता ने यह नहीं सोचा कि बड़ा सालों से परिवार का बोझ उठाए हुए है और अपना सब कुछ घर के लिए झोंक चुका है। बड़ा भाई और भाभी हमेशा छोटे के लिए खुद से अच्छा ढूंढते और सोचते रहे – कपड़ों से लेकर पढ़ाई और सुविधा तक, हर बार उन्होंने पहले छोटे की जरूरत पूरी की। लेकिन माता-पिता और छोटे की इच्छाओं को कभी सब्र नहीं मिला; जो चाहा, तुरंत चाहिए था, चाहे उसके लिए बड़े का त्याग और मेहनत क्यों न कुर्बान हो। बड़े भाई और उसकी पत्नी दोनों ड्यूटी करते और बच्चा पिता की गोद में पलता। इस वक्त भी न सास-ससुर, न बहनें और न ही छोटा भाई मदद को आगे आए। कुछ समय बाद छोटे भाई की शादी हुई। उसकी पत्नी भी नौकरी में थी। घर के कर्ज.को उतारने के बजाय दोनों ने नई गाड़ी खरीद ली। जबकि बड़े भाई की पत्नी को मायके से गाड़ी के लिए जो पैसे मिले थे, वे भी इस घर को आगे बढ़ाने में खर्च हो चुके थे।

सबसे चुभने वाली बात यह थी कि बहनों की पढ़ाई और जरूरतों के लिए सालों तक सबकुछ देने के बाद भी, वे छोटे भाई के पक्ष में रहीं। जैसे बड़े का हर त्याग, हर मेहनत किसी पुराने कपड़े की तरह बेमानी हो गया हो। अब घर का माहौल बदल चुका था। छोटा भाई और उसकी पत्नी के बीच अहम का भाव बढ़ चुका था। बातें तानों में बदल गई थीं।

नेपाल-चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सागरमाथा फ्रेंडशिप' 6 से 16 सितंबर तक काठमांडू में

एजेंसी

काठमांडू। नेपाली सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का पांचवां संस्करण सितंबर के पहले सप्ताह से नेपाल में होने वाला है। 'सागरमाथा फ्रेंडशिप' नामक यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी अभियानों, युद्ध रणनीति और आपदा प्रबंधन पर केंद्रित होगा। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्नेत ने बताया कि नेपाल और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 6 सितंबर से शुरू होगा और 16 सितंबर तक चलेगा। इस संयुक्त अभ्यास का चौथा संस्करण पिछले साल चीन के सिचुआन प्रांत के पास चोंगकिंग में हुआ था। इस बार दोनों सेनाओं के अधिकारी अभ्यास के तौर-तरीकों, प्रतिभागियों की संख्या और पर्यवेक्षकों को अंतिम रूप देने के लिए गहन चर्चा कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मनोज कुमार आचार्य ने संयुक्त अभ्यास को एक नियमित सैन्य सहयोग कार्यक्रम का हिस्सा बताया। आचार्य ने कहा कि नेपाल नियमित रूप से भारत, अमेरिका और चीन के साथ इस तरह के अभ्यास आयोजित करता है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से क्षमता बढ़ाने और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए यह सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के सचिव ने इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में किसी विशेष देश के लक्षित नहीं होने की बात स्पष्ट की है।

रूस में सेना के संयंत्र में विस्फोट, चार सैनिकों समेत 11 की मौत, 130 घायल

मॉस्को। रूस में सेना के एक बारूद संयंत्र में हुए विस्फोट में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 130 से अधिक घायल हो गए। मृतकों में रूस के चार सैनिक भी शामिल हैं। आपातकालीन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यह विस्फोट मॉस्को के दक्षिण-पूर्व में रियाजान क्षेत्र में स्थित एक संयंत्र में हुआ। रूस के अखबार द मास्को टाइम्स और यूक्रेन के डिजिटल मीडिया 'यूनाइडेट 24 मीडिया' ने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के हवाले खबर दी है कि यह इलास्टिक सिंथेटिक फाइबर संयंत्र है। इसके बारूद के ढेर में अचानक आग लग जाने से कई विस्फोट हुए। आपातकालीन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर संयंत्र के मलबे और इमारत को हुए भारी नुकसान की तस्वीरें अपलोड करते हुए घोषणा की, दुर्भाग्य से 11 लोग मारे गए। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि इस विस्फोट में 130 अन्य लोग घायल हो गए। रूसी आपातकालीन अधिकारियों के अनुसार, घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि रियाजान शहर से 65 किलोमीटर (40 मील) दक्षिण-पूर्व और मॉस्को से 250 किलोमीटर (155 मील) दक्षिण-पूर्व में स्थित लेस्नोय गांव में लगी आग की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। रियाजान क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों ने एक दिन के शोक की घोषणा की है।

कुवैत में जहरीली शराब पीने से 16 नेपाली नागरिकों की मौत

काठमांडू। कुवैत में जहरीली शराब पीने के कारण मरने वाले नेपाली नागरिकों की संख्या 16 पहुंच गई है। कुवैत स्थित नेपाली दूतावास ने कहा है कि जहरीली शराब पीने के बाद लगभग 35 नेपाली नागरिकों को कुवैत के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अस्पताल में भर्ती कुछ लोगों की हालत गंभीर है और कुछ की हालत सामान्य है। बयान में कहा गया है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद नेपाली मरीजों की स्थिति जानने के लिए विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया गया। दूतावास ने कहा कि वह इस घटना के संबंध में संबंधित अस्पताल और कुवैती स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है ताकि अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा सके। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मेथनॉल अल्कोहल के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। मंत्रालय के अनुसार, 160 से ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। कुवैत में नेपाली पत्रकार महासंघ की विदेश शाखा के अध्यक्ष एकराज मल्ला ने बताया कि अबतक मारे गए 23 लोगों में से 16 नेपाली नागरिक हैं और बाकी भारतीय नागरिक हैं।

रूस के साथ चल रहे साइबर युद्ध के बीच पोलैंड ने शहर की जल प्रणाली पर हमले को किया नाकाम

वारसॉ। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री क्रिजटोफ गॉवकोव्स्की ने खुलासा किया कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े शहर की पानी और सीवेज प्रणाली पर हुए साइबर हमले को नाकाम कर दिया। यह हमला 13 अगस्त को हुआ था और अगर समय पर रोका नहीं जाता, तो शहर को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ सकता था। गॉवकोव्स्की, जो डिजिटल मामलों के मंत्री भी हैं, ने बताया कि हमले की शुरुआत होते ही सुरक्षा सेवाओं ने सिस्टम को बंद कर नुकसान को रोक दिया। उन्होंने शहर का नाम उजागर करने से इनकार किया ताकि लोगों में घबराहट न फैले। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर हमलावरों का नाम नहीं लिया लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट में रूसी शत्रुता का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, 'रूसी विमान वारसॉ में नहीं आएंगे, न ही टैंक घुसेंगे – उनकी डिजिटल छाया आएगी।' उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे हमलों का पहला चरण पानी, गैस और बिजली की आपूर्ति काटना, संचार ठप करना या लॉजिस्टिक्स को रोकना हो सकता है।

पाकिस्तान में बाढ़ का कहर : खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड से 300 से ज्यादा लोगों की मौत

एजेंसी

पाकिस्तान । खैबर पख्तूनख्वा में मानसूनी बारिश कहर बन कर बरसी है। महज 48 घंटे में अचानक आई बाढ़ में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों की संख्या 307 है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के मुताबिक शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा में मरने वालों की संख्या 307 हो गई। इसमें गिलगित-बाल्टिस्तान में करीब 12 और पीओके में 9 लोगों की जान चली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में शुक्रवार को हुई भारी बारिश विनाशकारी रही। कई जिलों में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से अचानक आई बाढ़ में एक ही दिन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में प्रांतीय सरकारी हेलीकॉप्टर के पांच चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। हेलीकॉप्टर

राहत और बचाव कार्य के दौरान मोहमंद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डॉन (पाकिस्तानी मीडिया) की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 48 घंटों में 184 लोगों की जान गई है और बुनेर सबसे प्रभावित जिला रहा। शांगला में 36, मनसेहरा में 23, स्वात में 22, बाजौर में 21, बट्टाग्राम में 15, निचले दीर में पांच और एबटाबाद में एक बच्चे के डूबने की खबर है। बाढ़ के कारण 11 घर नष्ट हुए हैं जबकि 63 क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्वात और शांगला में सरकारी स्कूल प्रभावित हुए हैं। बुनेर के डीसी काशिफ कयूम खान ने भी डॉन से बातचीत में कहा कि चगरजई तहसील में 30 लोग लापता हैं, जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। बचाव दल का तलाशी अभियान जारी है। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने बुनेर, बाजौर, स्वात, शांगला, मनसेहरा और बट्टाग्राम जैसे गंभीर रूप से प्रभावित पर्वतीय जिलों को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। पाकिस्तान के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के मुताबिक लगभग 2,000 बचावकर्मी मलबे से शव निकालने और नौ प्रभावित जिलों में राहत अभियान चलाने में लगे हुए हैं। भारी बारिश, कई इलाकों में भूस्खलन और सड़कें बह जाने की वजह से सहायता पहुंचाने में, खासकर भारी मशीनरी और एम्बुलेंस पहुंचाने में मुश्किल हो रही है।

सीमा मुद्दों पर बातचीत के लिए भारत जाएंगे चीन के विदेश मंत्री वान्ग यी

एजेंसी

बीजिंग। चीन-भारत सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच 24वें दौर की वार्ता के लिए चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी 18 से 20 अगस्त तक भारत के दौरे पर जाएंगे। इस संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह दौरा भारतीय पक्ष के निमंत्रण पर हो रहा है। वांग यी, जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य भी हैं, सीमा मुद्दे पर भारत के विशेष प्रतिनिधि के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। यह वार्ता दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और सीमा क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीमा वार्ता की यह शृंखला दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक निरंतर प्रयास है।

पुतिन ने कहा, 'यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए', लेकिन केवल तभी जब रूस की चिंताएं पूरी हों

एजेंसी

एंकोरेज (अलास्का) । रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस बात पर सहमत हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसके साथ-साथ रूस की सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी चिंताओं का समाधान होना जरूरी है। अलास्का के एंकोरेज में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा, ÷मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं कि यूक्रेन की सुरक्षा जरूरी है और हम इस पर काम करने को तैयार हैं।÷ पुतिन ने उम्मीद जताई कि ट्रंप के साथ हुई बातचीत से यूक्रेन में शांति का रास्ता खुलेगा। पुतिन ने कहा कि युद्ध तभी खत्म हो सकता है जब इसके मूल कारणों को दूर किया जाए। उनका कहना था कि यूक्रेन का मामला सीधे-सीधे रूस की सुरक्षा से जुड़ा है और यूरोप व दुनिया में सुरक्षा का संतुलन बहाल करने के लिए रूस की चिंताओं पर ध्यान देना होगा। हालांकि पुतिन ने यह साफ नहीं किया कि मूल कारणों से उनका क्या आशय है। पहले भी उन्होंने इसे ऐसे मुद्दों से जोड़ा है जिन्हें कीव और उसके सहयोगी मानने को तैयार नहीं हुए। दूसरी ओर, ट्रंप ने बैठक के बाद कहा कि वह नाटो नेताओं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अन्य अधिकारियों को बातचीत की जानकारी देंगे। बैठक करीब तीन घंटे चली, जिसके बाद दोनों नेताओं ने प्रगति का दावा किया, लेकिन न तो युद्ध विराम की घोषणा की और न ही किसी मुद्दे पर विस्तार से बताया।

पुतिन ने बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया और ट्रंप का धन्यवाद किया कि बैठक मैत्रीपूर्ण और भरोसेमंद माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने नतीजे हासिल करने की गंभीरता दिखाई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुतिन ने अलास्का में अपनी बैठक में विश्वास के माहौल के लिए ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। रूसी समाचार एजेंसीकी रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने ट्रंप के साथ बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं ट्रंप को साथ मिलकर काम करने और बातचीत में एक दोस्ताना और भरोसेमंद माहौल बनाए रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्य बात यह है कि दोनों पक्ष परिणाम हासिल करने के लिए दृढ़ थे। पुतिन ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया। पुतिन ने यह भी कहा कि अलास्का में हुए समझौते भविष्य में यूक्रेन समस्या को सुलझाने और रूस-अमेरिका संबंधों को सुधारने की दिशा में अहम साबित हो सकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट आई है, लेकिन ट्रंप से उनकी बातचीत आपसी सम्मान और भरोसे के साथ हुई।

इस्लामाबाद में 32 दिन से बलोचों का धरना जारी

एजेंसी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत से लापता लोगों के परिजनों और बलोच यकजेहती समिति (बीवाईसी) के सदस्यों का इस्लामाबाद में धरना 32वें दिन में प्रवेश कर गया। बलोचिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों और बीवाईसी नेताओं को हिरासत में लेने की घटनाओं को दुनिया के सामने उजागर करने के मकसद से यह धरना आयोजित किया गया है। प्रदर्शनकारी जबरन गुमशुदगी को रोकने, हिरासत में लिए गए बलोच नेताओं को तुरंत अदालत में पेश करने और नागरिक स्वतंत्रता के सम्मान की मांग कर रहे हैं। द बलोचिस्तान पोस्ट के अनुसार, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर शुक्रवार को बीवाईसी नेतृत्व के तत्वावधान में 'गैरकानूनी हिरासत और जबरन गायब किए गए लोगों के परिवारों की शिकायतें' शीर्षक से एक सेमिनार का आयोजन होना था। धरने पर बैठे लोगों का दावा है कि पुलिस ने सेमिनार से कुछ घंटे पहले ही धावा बोल दिया। महिलाओं और बच्चों के साथ धक्कामुक्की की और उन पर हमला करके भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। इन लोगों ने बताया कि पुलिस ने प्रेस क्लब परिसर में प्रवेश रोकने के लिए अवरोधक लगाए और महिला प्रदर्शनकारियों के

प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हिरासत में लिए गए बीवाईसी नेता महरंग बलूच की बहन नादिया बलूच ने पत्रकारों से कहा, हम यहाँ अपना विरोध दर्ज कराने आए थे, लेकिन हमें अपना स्थान बदलने के लिए मजबूर किया गया। 14 अगस्त को हमारे लिए सड़कें खुली थीं, लेकिन 15 अगस्त को प्रेस क्लब जाने वाले सभी रास्ते फिर से बंद कर दिए गए। न केवल हमें रोका गया, बल्कि महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। प्रतिबंधों के बावजूद सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, छात्र और लापता लोगों के परिवार के सदस्य शामिल हुए। वक्ताओं ने बलोचिस्तान में दमन, जबरन गुमशुदगी, न्यायेतर हिरासत और मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों पर बात की। वक्ताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक अधिकार है और इसे दबाने के लिए बल प्रयोग गैरकानूनी और मानवीय गरिमा का अपमान है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति का ऐलान, 18 अगस्त को करेंगे ट्रंप से मुलाकात

एजेंसी

नई दिल्ली । यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वो 18 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी ये कोशिश यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने के इरादे से है। राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का के एंकोरेज में हुई बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया बातचीत का विवरण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए जाहिर किया। जेलेंस्की ने लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंबी और सार्थक बातचीत हुई। यूरोपीय नेताओं के शामिल होने से पहले हमने एक-दूसरे से बातचीत की। यह बातचीत डेढ़ घंटे से ज़्यादा समय तक चली, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मेरी लगभग एक घंटे की द्विपक्षीय बातचीत शामिल थी। यूक्रेन

शांति स्थापित करने के लिए पूरी ताकत से काम करने की अपनी तत्परता की पुष्टि करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे रूसी नेता के साथ अपनी बैठक और उनकी चर्चा के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प के त्रिपक्षीय वार्ता के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। उन्होंने आगे कहा, हम यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यूक्रेन इस बात पर जोर देता है कि प्रमुख मुद्दों पर नेताओं के स्तर पर चर्चा की जा सकती है, और इसके लिए त्रिपक्षीय प्रारूप उपयुक्त है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी आगामी बैठक की भी पुष्टि की। उन्होंने कहा, मैं वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलूंगा और युद्ध समाप्त करने संबंधित सभी विवरणों पर चर्चा करूंगा। मैं इस निमंत्रण के लिए आभारी हूं। यह अच्छी बात है कि अमेरिका के साथ मिलकर विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए यूरोप हर स्तर पर शामिल किया जा रहा है। हमने यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिकी पक्ष की भागीदारी के सकारात्मक संकेतों पर भी चर्चा की। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो हमारी मदद कर रहे हैं। इस बीच, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की।

नेपाल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह

एजेंसी

काठमांडू। भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को काठमांडू में भारतीय दूतावास, वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास एवं पोखरा तथा धरान में रहे भारतीय सेना के पेंशन कैंप में विभिन्न कार्यक्रम के साथ मनाया गया। काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास में इस कार्यक्रम की शुरुआत नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। इसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश को पढ़ा गया। इस अवसर पर भारतीय राजदूत ने भारतीय सशस्त्र बलों के मृत कर्मियों की विधवाओं और परिजनों को सम्मानित किया और उन्हें 6.4 करोड़ के कुल मूल्य के चेक हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा दूतावास ने नेपाल के 7 प्रांतों और 21 जिलों में फैले 39 शैक्षणिक संस्थानों और पुस्तकालयों के लिए पुस्तक अनुदान की भी घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों के लिए शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाना है। काठमांडू में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में नेपाल में भारतीय समुदाय के सदस्यों, भारत के मित्रों के साथ-साथ दूतावास के अधिकारियों और उनके परिवारों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इस अवसर पर दूतावास के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और केंद्रीय विद्यालय, काठमांडू के छात्रों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किए गए।

पुतिन के साथ समझौते की दिशा में 'शानदार प्रगति', जेलेंस्की और नाटो नेताओं से करेंगे बात : ट्रंप

एजेंसी

एंकोरेज (अलास्का) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात में 'कुछ प्रगति' हुई है और उन्होंने 'काफी अच्छी तरक्की' की है। हालांकि, ट्रंप ने यह भी साफ़ किया कि 'जब तक कोई समझौता हो नहीं जाता, तब तक उसे समझौता नहीं माना जा सकता।'

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अलास्का के एंकोरेज में हुई शिखर वार्ता के बाद ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही नाटो और अन्य जरूरी लोगों से बात करेंगे। वे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी अलास्का के शुक्रवार के सम्मेलन के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा, 'निर्णय उनके ऊपर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'हमारी बैठक बहुत अच्छी रही और

कई बिंदुओं पर सहमति बनी। हम अभी अंतिम समझौते तक नहीं पहुंचे, लेकिन इसके लिए अच्छा मौका है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को उन बातों से 'सहमत' होना होगा जिन पर विदेश मंत्री मार्को रुबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके प्रशासन के अन्य लोगों ने शुक्रवार को पुतिन के साथ चर्चा की थी। हालांकि, उन्होंने किसी समझौते के ढांचे के बारे में विस्तार से नहीं बताया ट्रंप और पुतिन ने अपने बयानों के बाद कोई सवाल नहीं लिया।

पुतिन ने पहले बोलना शुरू किया और करीब आठ मिनट तक बोले। ट्रंप, जो आमतौर पर लंबी और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने जाते हैं, केवल चार मिनट बोले। ट्रंप ने कहा, मैं अब कुछ फोन कॉल करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि क्या हुआ। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल के वर्षों में अमेरिका-रूस के संबंध खराब हुए हैं। आमतौर पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेशी नेता की मेजबानी करते हैं, तो पहले अमेरिकी नेता बोलते हैं, फिर मेहमान। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए युद्ध के मुख्य कारणों को दूर करना जरूरी है। उन्होंने यूक्रेनी और यूरोपीय नेताओं से उभरती प्रगति में दखल न देने को कहा।

बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए अमेरिका की निंदा की

एजेंसी

क्वेटा (बलूचिस्तान) पाकिस्तान। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) ने बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और उसकी विशेष शाखा मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) घोषित करने के अमेरिका के फैसले की निंदा की। बीआरजी ने कहा कि यह कदम पाकिस्तानी सरकार के बयान को दर्शाता है और बलूचिस्तान की वास्तविकताओं को नजरअंदाज करता है द बलूचिस्तान पोस्ट की खबर के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले सोमवार को बीएलए और उसकी विशेष इकाई मजीद ब्रिगेड को अपनी एफटीओ सूची में शामिल किया है। इस सूची के लागू होने से इन समूहों को भौतिक सहायता प्रदान करना अमेरिका में एक संघीय अपराध बन गया है।

अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में उनकी संपत्तियों को अवरुद्ध कर दिया गया है और सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान ने मंगलवार को इस कदम का स्वागत भी किया।

बीआरजी के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने कहा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को ऐसे फैसले लेने से पहले जमीनी हकीकत का आकलन करना चाहिए। उन्होंने मजीद ब्रिगेड को बलूचिस्तान की आजादी के व्यापक आंदोलन का हिस्सा बताया। दोस्तैन बलूच ने कहा कि बलूच राष्ट्र मजीद ब्रिगेड को अपना रक्षक और उसके लड़ाकों को 1948 से पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे का विरोध करने वाला नायक मानता है। उन्होंने कहा कि बलूचों का अपने संसाधनों पर पूरा अधिकार है। पाकिस्तान उनका दोहन करता है औरविदेशी ताकतों को बेच देता है।उन्होंने अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बलूच स्वतंत्रता आंदोलन को आतंकवाद से जोड़ने से बचने की सलाह दी है। बीआरजी प्रवक्ता ने कहा कि बलूच किसी भी विदेशी देश के खिलाफ नहीं हैं। वह अपने संसाधनों को लूटने में पाकिस्तान के साथ शामिल होने वाले किसी भी शक्ति का दृढ़ता से विरोध करेंगे। अमेरिका ने बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित करने में पाकिस्तानी के दुष्प्रचार पर विश्वास किया है।

प्रधानमंत्री ओली 16 सितंबर से भारत दौरे पर, पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता बोधगया में होगी

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 16 सितंबर से भारत दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में नहीं होगी, बल्कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता बिहार के बोधगया में होगी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 17 अगस्त को दो दिवसीय नेपाल यात्रा पर भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से काठमांडू पहुंचेंगे। वह प्रधानमंत्री ओली को भारत भ्रमण के लिए औपचारिक निमंत्रण पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ओली 16 सितंबर से भारत भ्रमण पर जाएंगे। आम तौर पर भारत भ्रमण पर पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों के साथ नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होने की परंपरा है। खास मौकों पर भी प्रधानमंत्री मोदी देश के अलग-अलग स्थानों पर भी इस तरह की बैठकें करते रहे हैं। इस बार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में नहीं होगी, बल्कि बिहार के बोधगया में द्विपक्षीय वार्ता होना तय हुआ है। नेपाल और भारत के प्रधानमंत्री के बीच बोधगया में द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

ट्रंप, पुतिन ने यूक्रेन पर तीन घंटे की बातचीत के बाद बड़ी सफलता की घोषणा की

एजेंसी

न्यूयॉर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को अलास्का के एंकोरेज में तीन घंटे की वार्ता के बाद बड़ी सफलता की घोषणा की। ट्रंप ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं, वह हमें उस लक्ष्य (समाधान खोजने) के और करीब लाने में मदद करेगा और यूक्रेन में शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुझे लगता है कि हमारी बैठक बहुत ही उपयोगी रही। ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर हम (राष्ट्रपति पुतिन और मैं) सहमत हुए।

यह समझौता भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यूएस ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क की घोषणा की है। हालांकि, अभी किसी भी नेता ने समझौते का कोई विवरण नहीं दिया और न ही यह बताया कि युद्धविराम होगा या नहीं।

ट्रंप ने रहस्यमय ढंग से कहा, कुछ बड़े समझौते ऐसे हैं जिन तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हमने कुछ प्रगति की है। एक समझौता शायद सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे पास उस तक पहुंचने की बहुत अच्छी संभावना है। हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे पास वहां पहुंचने की बहुत अच्छी संभावना है। उन्होंने कहा, मैं नाटो और उन सभी लोगों को फोन करूंगा जिन्हें मैं उपयुक्त समझता हूं, और निश्चित रूप से, राष्ट्रपति (वोलोदिमिर) जेलेंस्की को फोन करके उन्हें आज की बैठक के बारे में बताऊंगा। शिखर सम्मेलन में जाते हुए, ट्रंप ने कहा कि वह यूक्रेन की ओर से बातचीत नहीं करेंगे, और समझौता करना जेलेंस्की पर निर्भर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसलिए जब तक समझौता नहीं हो जाता, तब तक कोई

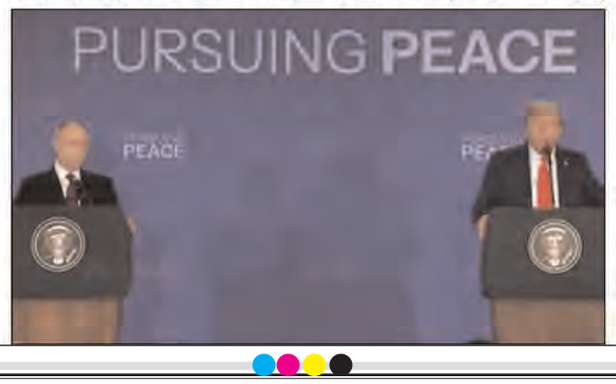

समझौता नहीं है। दोनों राष्ट्रपतियों ने पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए। पुतिन ने कहा, हमें टकराव से बातचीत की ओर बढ़ने के लिए स्थिति में सुधार करना होगा। उन्होंने कहा, इन परिस्थितियों में यह कितना भी अजीब लगे, हमारी (रूस और यूक्रेन की) जड़ें एक ही हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए एक त्रासदी और एक भयानक घाव है। इसलिए, देश ईमानदारी से इसे समाप्त करने में रुचि रखता है। शिखर सम्मेलन की शुरुआत में पहले से तय तीन चरणों को बदलकर, वे सीधे दूसरे चरण में चले गए। इस चरण में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्री मार्को रुबियो, और पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूडी उषाकोवा, रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव, और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हिस्सा लिया।ऐसा नहीं लग रहा था कि अधिकारियों के साथ तीसरे चरण का लंच हो रहा था। ट्रंप ने पुतिन का रेड कार्पेट पर स्वागत किया और लिमोजीन में बैठते ही उन्होंने दोस्ताना अंदाज में बातचीत जारी रखी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने विभिन्न निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ किया समझौता

नई दिल्ली। । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण सुविधा कार्यक्रम के तहत विभिन्न निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य एमएसएमई को सहायता प्रदान करना और उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में मदद करना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता, पहुंच एवं वहनीयता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने अपने एमएसएमई ऋण सुविधा कार्यक्रम के तहत 11 अगस्त को विभिन्न निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इनमें एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटक बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक मुख्य रूप से शामिल हैं। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और एमएसएमई सचिव एससीएल दास उपस्थित रहे। एनएसआईसी के निदेशक (वित्त) गौरव गुलाटी और विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। इस मौके पर संयुक्त सचिव (एसएमई) मर्सी एपाओ, एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. एसएस आचार्य तथा एनएसआईसी और बैंकों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बढ़त के साथ लिस्टिंग के बाद फिसले जेएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयर

नई दिल्ली। ग्रे सीमेंट बनाने वाली जेएसडब्ल्यू ग्रुप की सीमेंट कंपनी जेएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मामूली बढ़त के साथ एंट्री की। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 147 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 153 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 153.50 रुपये के स्तर पर हुई। इस तरह स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के बाद कंपनी के आईपीओ निवेशकों को करीब 4 प्रतिशत का ही लिस्टिंग गेन मिल सका। लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण कंपनी के शेयरों में गिरावट आ गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद जेएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयर 146.05 रुपये के स्तर पर बंद हुए। इस तरह स्टॉक मार्केट में बढ़त के साथ कारोबार करने के बावजूद पहले दिन ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 0.65 प्रतिशत का नुकसान हो गया। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का 3,600 करोड़ रुपये का आईपीओ 7 से 11 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 8.22 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 16.71 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

एसएंडपी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग को बढ़ाकर किया 'बीबीबी'

नई दिल्ली। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की साख एक पायदान बीबीबी-' से बढ़ाकर 'बीबीबी' कर दी है। एजेंसी ने महंगाई पर अंकुश लगाने वाले बेहतर मौद्रिक नीति उपायों के साथ मजबूत आर्थिक वृद्धि का हवाला देते हुई भारत की रेटिंग बढ़ाई है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने जारी एक बयान में कहा कि भारत की दीर्घकालीन 'सॉवरेन' साख को 'बीबीबी-' से बढ़ाकर 'बीबीबी' और अल्पकालिक रेटिंग को 'ए-3' से बढ़ाकर 'ए-2' कर

दिया है। दीर्घकालिक रेटिंग की बात करें, तो फिलहाल परिदृश्य स्थिर है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का असर प्रबंधित किए जा सकने वाले दायरे में होगा। एजेंसी ने कहा कि भारत व्यापार पर अपेक्षाकृत कम निर्भर है और इसकी लगभग 60 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि घरेलू खपत से आती है। हालांकि, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन 50 फीसदी शुल्क (यदि लगाया जाता है) से वृद्धि पर कोई बड़ा असर पड़ने की आशंका नहीं है।

मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज का आईपीओ 20 अगस्त को खुलेगा, प्राइस बैंड 533-561 रुपये प्रति शेयर

मुंबई। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 20 अगस्त को खुलेगा। निवेशक इसमें निवेश करने के लिए 22 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं। इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 533-561 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुताबिक निवेशक इसके लिए न्यूनतम 26 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 26 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं। कंपनी का 10 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य वाला ये इश्यू पूरी तरह फ्रेश है। कंपनी इसके जरिए 400 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की योजना नए निर्गम से प्राप्त राशि में से 101.27 करोड़ रुपये लिए गए कुछ बकाया उधारों, 87.86 करोड़ रुपये राजस्थान के सीकर जिले के रींगस स्थित यूनिट ढ्ढ्ढ में सुविधा के विस्तार करने, 122 करोड़ रुपये कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। ट्रांसफॉर्मर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ट्रांसफार्मर घटकों के प्रसंस्करण में विशेषज्ञता रखती है, जिसमें ट्रांसफार्मर लेमिनेशन, सीआरजीओ स्लिट कॉइल, एमोर्फस कोर, कॉइल और कोर असेंबली, वाउन्ड और टॉरॉयडल कोर, और ऑयल-इमर्सड सर्किट ब्रेकर शामिल हैं। ये कंपनी सीआरजीओ और सीआरएनओ कॉइल के साथ-साथ एमोर्फस रिबन का भी व्यापार करती है।

सरकार ने जीएसटी की पांच और 18 फीसदी की सिर्फ दो कर दरों का रखा प्रस्ताव

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की संशोधित व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इस नए ढांचे में पांच फीसदी, 18 फीसदी वाली सिर्फ दो टैक?स दरों का ही प्रस्ताव रखा है, जबकि लग्जरी और हानिकारक (शराब और तंबाकू, ड्रग्स, जुआ इत्यादि) वस्तुओं पर 40 फीसदी का विशेष टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इसे दिवाली तक लागू हो जाने का अनुमान है।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस साल दिवाली तक मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह लेने के लिए संशोधित प्रारूप में दो स्लैब वाली जीएसटी दर संरचना और कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष टैक?स की दरों का प्रस्ताव दिया है। वित?त मंत्रालय ने जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह

(जीओएम) को अपना ये प्रस्ताव भेजा है। इसमें 12 और 28 फीसदी की मौजूदा कर दरों को हटा दिया गया है। इसके अलावा जीएमओ को भेजे प्रस्ताव में लग्जरी और हानिकारक (शराब और तंबाकू, ड्रग्स, जुआ इत्यादि) वस्तुओं पर 40 फीसदी तक का विशेष टैक्स लगाने की तैयारी है। जीएसटी का ये नया टैक्स इस साल दीवाली से पहले लागू करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा 12 फीसदी जीएसटी स्लैब में आने वाली लगभग 99 फीसदी वस्तुएं अब 5 फीसदी वाले स्लैब में चली जाएंगी। वहीं, 28 फीसदी वाले स्लैब में आने वाली लगभग 90 फीसदी वस्तुएं अब 18 फीसदी वाले स्लैब में आ जाएंगी। इस बदलाव से टैक्स संरचना सरल होगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लालकिले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जीएसटी की दरों को लेकर ऐलान के बाद यह कवायद शुरू की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंत्रियों के समूह (जीओएम) को दो स्लैब वाली जीएसटी टैक?स दर संरचना और कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष दरों का प्रस्ताव भेजा है। देश में फिलहाल जीएसटी की 0 फीसदी टैक्स दर जरूरी खाद्य वस्तुओं पर, 5 फीसदी की दर रोजमर्रा की चीजों पर, 12 फीसदी सामान्य सामानों पर, 18 फीसदी सेवाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पर और 28 फीसदी लग्जरी/हानिकारक वस्तुओं पर लगता है।

वित्त मंत्रालय ने दो स्लैब वाली जीएसटी दर संरचना का दिया प्रस्ताव

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को लेकर बड़ा ऐलान किया। इस घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने कहा कि मंत्रियों के समूह (जीओएम) को दो स्लैब वाली जीएसटी दर संरचना और कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष दरों का प्रस्ताव दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा कि जीएसटी सुधार दीपावली तक लागू हो जाएंगे, जिससे कर का बोझ काफी कम होगा और छोटे उद्योगों को लाभ होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीओएम के साथ इस प्रस्ताव को साझा किया गया है।वित त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार का प्रस्ताव तीन बिंदुओं पर आधारित है, संरचनात्मक सुधार, दरों को युक्तिसंगत बनाना और जीवन को आसान बनाना। मंत्रालय के प्रस्ताव में आम आदमी की जरूरत की वस्तुओं और आकांक्षात्मक वस्तुओं पर करों में कमी शामिल है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी प्रणाली के तहत दो स्लैब 'मानक और योग्यता' का

प्रस्ताव दिया है, जबकि विशेष दरें केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर ही लागू होंगी। इस समय जीएसटी की 5, 12, 18 और 28 फीसदी की चार स्तरीय संरचना है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की बैठक सितंबर में होने की उम्मीद है, जिसमें दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए मंत्रिसमूह के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

व्यापार एवं उद्योग जगत ने जीएसटी में सुधार लाने की घोषणा का स्वागत किया

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में व्यापक सुधार करने की घोषणा का देश के व्यापारिक समुदाय ने जोरदार स्वागत एवं सराहना की है। व्यापारियों का मानना है कि यह बदलाव आम नागरिकों पर कर बोझ को कम करने और खपत को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री मोदी की जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने की घोषणा का स्वागत करते हुए भाजपा सांसद एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ये साहसिक कदम भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। खंडेलवाल ने बताया कि रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाने और कर स्लैब को सरल

बनाने का यह कदम छोटे व्यापारियों, एमएसएमई और खुदरा क्षेत्र के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा तथा त्योहारों के मौसम से पहले अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित जीएसटी दरों का युक्तिकरण, विशेषकर जरूरी और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर में कटौती सीधे आम नागरिकों को फायदा पहुंचाएगी। यह क्रय शक्ति बढ़ाएगी और छोटे व्यापारियों एवं एमएसएमई को राहत प्रदान करेगी।

कैट महामंत्री खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी में यह सुधार कर संरचना को सरल बनाएगा, अनुपालन के बोझ को कम करेगा। इसके साथ ही सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग के एजेंडे को मजबूती प्रदान करेगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप जीएसटी को ढालकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर समावेशी विकास, घरेलू व्यापार सशक्तीकरण और भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है।

सर्राफा बाजार में लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ सोना, चांदी की बढ़ी कीमत

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में लगातार चौथे दिन सोने की कीमत में मामूली गिरावट का रुख नजर आ रहा है। दूसरी ओर चांदी के भाव में आज मामूली तेजी दर्ज की गई है। कीमत में गिरावट आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,01,340 से लेकर 1,01,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 92,890 रुपये से लेकर 93,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोना के विपरीत चांदी के भाव में मामूली तेजी आने के कारण कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,16,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,01,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 93,040 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,01,340 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,01,390 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,940 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,01,340 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 92,890 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,01,340 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 92,890 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,01,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 93,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 92,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,01,490 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 93,040 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोना सस्ता हुआ है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 1,01,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

स्टॉक मार्केट में मजबूत लिस्टिंग के बाद फिसले कॉनप्लेक्स सिनेमाज के शेयर

एजेंसी

नई दिल्ली। एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनी कॉनप्लेक्स सिनेमाज के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में मजबूती के साथ एंट्री की। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 177 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 10.17 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 195 रुपये के स्तर पर हुई। हालांकि लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण आईपीओ निवेशकों की खुशी फीकी पड़ गई। पूरे दिन का कारोबार होने के बाद कॉनप्लेक्स सिनेमाज के शेयर 186.90 रुपये के स्तर पर बंद हुए। इस तरह पहले दिन के कारोबार के बाद कंपनी के आईपीओ निवेशकों का मुनाफा घट कर 5.59 प्रतिशत रह गया। कॉनप्लेक्स सिनेमाज का 90.27 करोड़ रुपये का आईपीओ 7 से 11 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से जोरदार रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये

ओवरऑल 35.67 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 44.21 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 49.75 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 24.75 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 51 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने कॉरपोरेट ऑफिस की खरीदारी करने, एलईडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर्स की खरीदारी करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 1.65 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 4.09 करोड़ रुपये और 2024-25 में उछल कर 19.01 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व 91 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 96.78 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

स्टॉक मार्केट में मजबूत एंट्री के बाद फिसले ऑल टाइम प्लास्टिक्स के शेयर

एजेंसी

नई दिल्ली। घरों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ऑल टाइम प्लास्टिक्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री की। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 275 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 314.30 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 311.30 रुपये के स्तर पर हुई। इस तरह स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के साथ ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को करीब 14 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन मिल गया। हालांकि लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण कुछ ही देर में कंपनी के शेयर फिसलने लगे। पूरे दिन के कारोबार के बाद ऑल टाइम प्लास्टिक्स के शेयर 283.25 रुपये के स्तर पर बंद हुए। इस तरह पहले दिन के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों का मुनाफी घट कर 3 प्रतिशत रह गया। ऑल टाइम प्लास्टिक्स का 400.70 करोड़ रुपये का आईपीओ 7 से 11 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 8.62 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 10.30 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 14.01 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 5.36 गुना और एंप्लॉयीज के लिए रिजर्व पोर्शन 7.81 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के तहत 280.09 करोड़ रुपये के 1,01,81,818 नए शेयर जारी किए गए हैं। इसके अलावा 2 रुपये फेस वैल्यू वाले 43,85,562 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे गए हैं।

देश का निर्यात जुलाई में 7.29 फीसदी बढ़कर 37.24 अरब डॉलर पर

एजेंसी

नई दिल्ली। अर्थव्यस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच देश का निर्यात जुलाई में सालाना आधार पर 7.29 फीसदी बढ़कर 37.24 अरब डॉलर पर पहुंच गया। लेकिन, आयात बढ़ने से व्यापार घाटा आठ महीने के उच्चतम स्तर 27.35 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को जारी आंकड़ों में बताया कि जुलाई में देश का वस्तु निर्यात दो महीने की लगातार गिरावट के बाद रफ्तार पकड़ते हुए 37.24 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल की समान अवधि में देश का निर्यात 34.71 अरब डॉलर रहा था। वहीं, जुलाई में देश का आयात 8.6 फीसदी बढ़कर 64.59 अरब डॉलर

हो गया। इस वजह से व्यापार घाटा (निर्यात एवं आयात) के बीच का फासला बढ़कर 27.35 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो नवंबर, 2024 के बाद सबसे ज्यादा है।

मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान देश का निर्यात 3.07 फीसदी बढ़कर 149.2 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 5.36 फीसदी बढ़कर 244.01 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस तरह पिछले चार महीने की अवधि में कुल व्यापार घाटा 94.81 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने इन आंकड़ों पर कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद देश का वस्तु एवं सेवा निर्यात बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक निर्यात वृद्धि की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है। बर्थवाल ने कहा कि निर्यात के बेहतर आंकड़ों के पीछे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, दवा और रसायन क्षेत्रों का बड़ा योगदान रहा है।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 15 अगस्त को 51 नई शाखाएं खोलेगा

एजेंसी

नई दिल्ली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए तैयार है। बैंक ने देशभर में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 51 नई शाखाएं खोलने की घोषणा की है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जारी एक बयान में कहा कि देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को इन 51 नई शाखाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इस विस्तार में उच्च-संभावित क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित देयता और एमएफआईबी शाखाएं भी शामिल हैं। बयान के मुताबिक ये नई शाखाएं जमा, भुगतान, संग्रहण समाधान, व्यापार वित्त, बीमा, निवेश उत्पाद और उन्नत डिजिटल बैंकिंग सहित वित्तीय सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करेंगी। इसके अतिरिक्त, एमएफआईबी शाखाएं सूक्ष्म उद्यमों और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता प्रदान करेंगी। बैंक ने कहा कि इन विस्तार में 30 देयता शाखाएं और 21 माइक्रोफाइनेंस एवं समावेशी बैंकिंग (एमएफआईबी) शाखाएं शामिल हैं, जो पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे उच्च-संभावना वाले क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित हैं। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पिछले हफ्ते ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्मॉल

फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जयपुर स्थित एक भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक लघु वित्त बैंक है। इसकी स्थापना 1996 में एक वाहन वित्त कंपनी के रूप में हुई थी, जिसे 2017 में एक लघु वित्त बैंक में परिवर्तित कर दिया गया।

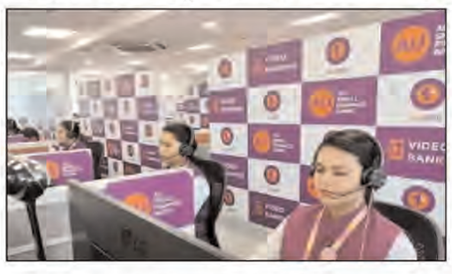

नोएल टाटा बने टाटा संस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर

एजेंसी

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक टाटा समूह की कंपनी टाटा संस ने नोएल टाटा को बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया है। कंपनी की 107वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में

इसकी मंजूरी दी गई। ये रतन टाटा के निधन के बाद टाटा सन्स की पहली जनरल मीटिंग है। कंपनी ने जारी एक बयान में कहा कि टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा की टाटा संस के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। कंपनी की 107वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। नोएल टाटा पिछले साल अक्टूबर में रतन टाटा के देहांत के बाद से टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। नोएल टाटा अब अधिकारिक रूप से टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। टाटा ट्रस्ट टाटा संस में 66 फीसदी हिस्सेदारी रखता है, जो टाटा समूह के कामकाज के महत्वपूर्ण निर्णय लेता है।

डॉलर की तुलना में 9 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ रुपया

एजेंसी

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमत में आई तेजी, आयातकों की ओर से बढ़ती डॉलर की मांग और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपया आज एक बार फिर डॉलर की तुलना में गिरावट का शिकार हो गया। आज डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा 9 पैसे फिसल कर 87.55 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय मुद्रा 87.46 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत भी सांकेतिक गिरावट के साथ ही की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की कमजोरी के साथ 87.47 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के कुछ देर बाद डॉलर की आवक बढ़ने के कारण रुपया 8 पैसे की मजबूती के साथ 87.38 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद बाजार में आयातकों ने डॉलर की मांग बढ़ा दी।

इसके साथ ही विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में बिकवाली शुरू करके रुपये पर और दबाव बना दिया। ऐसे नकारात्मक माहौल के कारण रुपया ऊपरी स्तर से 30 पैसे की गिरावट के साथ 87.68 के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, दोपहर 12 बजे के बाद मुद्रा बाजार की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, जिसके कारण भारतीय मुद्रा ने निचले स्तर से 13 पैसे की रिकवरी करके 9 पैसे की कमजोरी के साथ 87.55 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर आज के कारोबार का अंत किया। फौरेक्स मार्केट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों द्वारा की जा रही बिकवाली ने तो रुपये पर पहले ही दबाव बना रखा है। अब कच्चे तेल की कीमत में आई तेजी के कारण मार्केट सेंटिमेंट्स पर और भी निगेटिव असर पड़ा है। इसके साथ ही आयातकों ने भी पेमेंट ऑब्लिगेशंस के कारण डॉलर की मांग बढ़ा दी है। इसकी वजह से डॉलर में आज तेजी का रुख बन गया है। मुद्रा कारोबारी अंशुमान चौधरी का कहना है कि 15 अगस्त को होने वाली अमेरिका-रूस वार्ता से पहले निवेशक प्रतीक्षा और निगरानी की स्थिति में हैं। इस वार्ता के नतीजों का असर भारत के साथ ही पूरी दनिया के बाजारों पर पड़ेगा। बाजार की गतिविधियों की वजह से मुद्रा बाजार भी प्रभावित हो सकता है।मुद्रा बाजार में आज के कारोबार के बाद ब्रिटिश पौंड (जीबीपी) की तुलना में रुपया 17 पैसे की कमजोरी के साथ 118.90 के स्तर तक गिर गया। इसी तरह यूरो की तुलना में रुपया आज 28 पैसे की उछाल के साथ 102.30 के स्तर तक पहुंच गया।

कर्मचारियों के लिए सैलरी हाइक से ज्यादा

ये चीज है महत्वपूर्ण

एक सर्वे के मुताबिक कंपनियों के रोजगार का मूल्यांकन करने पर देखा गया कि कर्मचारियों के लिए अच्छा वर्क कल्चर, सेलरी हाइक से ज्यादा बड़ा आकर्षण हैं। जॉबबज.इन द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक 90 प्रतिशत वर्किंग प्रोफेशनल्स ने कहा है कि वे ऐसी कंपनी में ज्यादा बड़ी सेलरी पर भी काम करना पसंद नहीं करेंगे जहां का वर्किंग कल्चर खराब है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सीनियर कर्मचारी वह कंपनी चुनते हैं जो कि सक्रिय रूप से अच्छा वर्क कल्चर प्रमोट करती हो लेकिन ऐसा जूनियर लेवल पर नहीं हैं। सर्वे के मुताबिक 66 प्रतिशत लोगों ने बुरे वर्क कल्चर का दोषी टॉप मैनेजमेंट को माना है। उनके मुताबिक बॉस को 12 प्रतिशत और एचआर को 11 प्रतिशत दोषी माना है। बचे हुए 11 प्रतिशत में उन्होंने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को नेगेटिव वर्ककल्चर के लिए जिम्मेदार माना है। सर्वे के मुताबिक 65 प्रतिशत लोग उस कॉर्पोरेट कल्चर को हाइलाइट न करने वाली कंपनी की तुलना में उस कंपनी में काम करना पसंद करेंगे जो सक्रिय रूप से वर्क कल्चर को प्रमोट करती है।

जानवरों से करते हैं प्यार

तो करियर होगा बेहतर

वह नौकरी करना ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें अच्छी सैलरी ही नहीं मिले बल्कि आपका हर दिन एक्साइटमेंट से भरा हो। यह तब ही हो सकता है जब वह जॉब आपकी रुचि का हो। ऐसा ही कुछ एनिमल लवर्स के साथ है। अगर आप जानवरों से विशेष लगाव रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं तो आपके लिए यहां भी करियर के कई विकल्प हैं जो आपको आपकी रुचि से जोड़े रहेंगे।

अगर आप जानवरों की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग तरह की स्कूलिंग और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन पहली आपको निश्चित करना होगा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उस मुताबिक आप स्किल्स, सर्टिफिकेट्स और एजुकेशन लेकर आप करियर बना सकते हैं।

वेटरनेरीयन बतौर आप खुद का एनिमल हॉस्पिटल, क्लिनिक खोल सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं। वेटरनेरीयन बनकर आप अच्छी इनकम के साथ अपने समाज में जानवरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए योगदान दे सकते हैं। वाइल्डलाइफ बायोलॉजिस्ट बनना उन लोगों के लिए अच्छा करियर विकल्प है जो जानवरों और विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं। ग्रूमर बनने का करियर विकल्प उन लोगों के लिए बेस्ट है जो प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा समय जानवरों को लाड़-प्यार में बिताते हैं। बड़ी कंपनियों में इसमें सैलरी भले ही बहुत ज्यादा न हो लेकिन बिजनेस माइंड के इस क्षेत्र में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और खुद की डॉग ग्रूमिंग कंपनी खोल सकते हैं। डॉग ग्रूमर की तरह डॉग वॉकर उनके लिए बनना बेहतर है जो कि खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं। यहां बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं है जो कि डॉक वॉकर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है लेकिन ऐसे कई पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जो प्रोफेशन को हायर करना पसंद करते हैं। खुद का डॉग वॉकिंग बिजनेस और क्लाइंट बेस तैयार कर आप कई डॉगीज के साथ पूरा दिन भी बिताते हैं। जूलॉजिस्ट बनना उनके लिए बेहतर है जो प्रत्यक्ष रूप से जानवरों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की इच्छा रखते हैं या उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। कई जूलॉजिस्ट जू में काम करते हैं और जानवरों की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं। अन्य जूलॉजिस्ट किसी जानवरी की प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं। वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर एक एडवेंचर जॉब हो सकता है जो कि जानवरों और फोटोग्राफी दोनों से खास लगाव रखते हों। वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर को ट्रेवलिंग काफी करनी होती है और अपना खूब समय देना होता है। कई घंटों की मेहनत के बाद कई शॉर्ट्स मिलते हैं। वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर बड़े पब्लिकेशन के लिए काम कर सकते हैं। यह जॉब उनके लिए है जो पालतू जानवरों को प्यार करते हैं। यह एन्टरप्रेन्योरशिप से जुडा है। खुद का पेट सिटिंग बिजनेस लेकर आप जानवरों के करीब रहेंगे।

बीपीओ/केपीओ में करियर की संभावनाएं

बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग)/केपीओ (नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग) उद्योग ने भारतीय युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसने न केवल हज़ारों लोगों को नौकरी प्रदान की है बल्कि उन्हें बेहतरीन वेतनमान के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वातावरण में काम करने का मौका भी प्रदान किया है। ये कम्पनियां भारतीय युवाओं को आकर्षक पैकेज के साथ नौकरी पर रखकर उनसे विभिन्न देशों में बैठे अपने ग्राहकों के लिए कार्य कराती हैं। सरल भाषा में कहें तो एक बीपीओ कंपनी अपने विदेशी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय युवाओं को नौकरी पर रखती है।

ये कम्पनियां अपने भारतीय संसाधनों द्वारा डाटा-एंट्री, मेडिकल ट्रान्सक्रिप्शन, कंटेंट राइटिंग, एचआर व वित्तीय सेवा जैसे कार्य कराती हैं। बीपीओ शब्द जहां इस क्षेत्र में होने वाले सभी तरह के व्यवसाओं के लिए प्रयुक्त होता है वहीं केपीओ ज्ञान व सूचना आधारित सेवाओं से जुड़ा होता है व इसके लिए उच्च शिक्षा का होना जरूरी है। केपीओ सेवा के कुछ उदाहरण हैं - कानूनी सेवा, बौद्धिक सम्पदा एवं पेटेंट से जुडी सेवाएं, अभियांत्रिकी सेवाएं, वेब डेवलपमेंट, कैड/कैम अनुप्रयोग, व्यापार अनुसंधान एवं विश्लेषण, कानूनी अनुसन्धान, चिकित्सा अनुसंधान, प्रकाशन और विपणन अनुसंधान (मार्केट रिसर्च केपीओ)। बीपीओ में कार्य करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शिक्षित व अनुभवी होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने बाद सीधे यहाँ नौकरी पा सकते हैं। यहां चुनौती अपने कार्य में ज्यादा तेज़ एवं प्रोफेशनल होने की है। आपको शिफ्ट में काम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपमें संवाद क्षमता है तो आप ग्राहक सेवा के क्षेत्र से शुरूआत कर सकते हैं। यदि आप आईटी में तकनीकी रूप से सक्षम हैं तो आप टेक्नीकल सपोर्ट प्रोफेशनल जैसे पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीपीओ की अपेक्षा केपीओं में अधिक शिक्षित एवं योग्य व्यक्तिओं की ज़रुरत होते है। एक बीपीओ में डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग, डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग, टेक्नीकल सपोर्ट एवं ग्राहक सेवा जैसे कार्य किये जाते हैं जबकि केपीओ में अनुसंधान और विकास, वित्तीय सलाह व सेवाएं, आधुनिक वेब एप्लीकेशन, व्यवसायिक और तकनीकी विश्लेषण, लर्निंग सॉल्यूशन, एनीमेशन और डिजाइन, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, औषधि और जैव तकनीकी, चिकित्सा सेवाएं, राइटिंग एंड कॉन्टेंट डेवेलपमेंट, कानूनी सेवाएं, बौद्धिक सम्पदा अनुसंधान, डाटा विश्लेषण, नेटवर्क मैनेजमेंट तथा प्रशिक्षण एवं सलाह जैसे विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में काम किया जाता है। इसलिए केपीओ में जॉब के लिए आपको क्षेत्र विशेष का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है तथा पार्ट-टाइम जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बीपीओ सबसे अच्छा विकल्प है। आप वहां कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, टेक्नीकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अथवा प्रोसेस एग्जीक्यूटिव जैसे पदों पर शुरूआत में अपने जेब-खर्चे के लायक एक अच्छी-खासी सैलेरी प्राप्त कर सकते हैं। कॉलेज के दिनों से ही बीपीओ ज्वाइन करने पर आपको कम उम्र में ही वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने का साहस एवं समझ विकसित हो जाती है।

इंटरव्यू में इस तरह दें महत्वपूर्ण सवालों के जवाब...

इस सवाल को कहानी की तरह बताने के बजाय इसके शॉर्ट और क्रिस्प रखें। इंटरव्यूअर को अपनी स्ट्रेंथ, अचीवमेंट्स और स्किल्स के बारे में बताएं। इससे इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि किस तरह से आप कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होंगे।

आप नौकरी क्यों बदलना चाहते हैं ?

हर एम्प्लॉयर जानना चाहता है कि कैंडिडेट ने अपनी पिछली नौकरी किन कारणों से छोड़ी थी। इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब आप अपने भविष्य पर फोकस्ड होकर दे सकते हैं। अपने पिछली कंपनी के बारे में निगेटिव बोलने की बजाए उसकी पॉजिटिव साइड को हाइलाइट करें और अपने एम्प्लॉयर की कोई निगेटिव इमेज सामने न रखें।

अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह परिभाषित करेंगे?

यह सवाल कैंडिडेट्स के लिए अवसर होता है कि वह इंटरव्यूअर के सामने अपना बेस्ट साइड रख सकें। इस सवाल से इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप उनकी कंपनी के लिए किस तरह रिलिवेंट एम्प्लॉई साबित होंगे। इसलिए इस सवाल का जवाब बहुत ध्यान से दें और अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ और स्किल्स को शोकेस करें।

आपका 5 साल बाद का करियर ग्राफ ?

इस सवाल से इंटरव्यूअर आपको भविष्य के लिए वास्तविक उम्मीदों के बारे में जानना चाहता है। अच्छा होगा कि आप इस सवाल का जवाब अपनी करियर ग्रोथ को सामने रखकर दें। इंटरव्यूअर को आप अपने करियर के लिए मोटिवेटेड और फोकस्ड लगने चाहिए।

आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं ?

इस सवाल से एम्प्लॉयर आपकी प्रायोरिटीज के बारे में जानना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ, इस सवाल का जवाब देते वक्त बेहतर होगा कि आप एम्प्लॉयर को अपनी जरूरतों का एक रीजनेबल आइडिया दे दें। अगर आप अपनी स्किल्स को लेकर श्योर हैं तो इस सवाल में किसी तरह का समझौता न करें।

यमुना बाजार में घुटनों तक भरे पानी में उतरीं सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को यमुना बाजार के बाढ़ प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना की स्थिति नियंत्रण में है। सुबह यमुना का जलस्तर 206 मीटर के करीब था लेकिन यह अभी उस निशान को पार नही कर पाया है। पानी एक दो दिन में कम हो जाएगा। सरकार प्रभावित इलाके के लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। हम दिल्ली में बाढ़ जैसे हालत नहीं बनने देंगे। गुप्ता ने कहा कि ये यमुना बाढ़ क्षेत्र का सबसे निचले इलाका है जहां मकान बसे हुए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि लोग घरों को खाली कर दें ताकि बाढ़ से उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम से लगातार हालात की निगरानी की जा रही है। राहत और बचाव दल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्लीवासियों को आश्वस्त करना चाहती हैं कि सरकार हर कदम पर जनता के साथ खड़ी है। दिल्लीवासियों की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को यमुना किनारे स्थित कई स्थानों का दौरा। उन्होंने यमुना व इससे सटे इलाकों में बाढ़ की स्थिति से निपटने की अधिकारियों से बातचीत कर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ऐसी तैयारी की है कि दिल्ली में यमुना से बाढ़ नहीं आएगी। दिल्ली पुलिस और डीडीएमए की राहत बचाव टीमों ने यमुना के किनारे की झुग्गियों में सर्च ऑपरेशन चलाया। प्रशासन ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र से सभी को बाहर निकाला। पूर्वी दिल्ली में गीता कॉलोनी के पास बंध रोड पर बने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 24 घंटे यमुना के जलस्तर की निगरानी हो रही है।

केंद्र ने कच्चे कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी

कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चे माल कपास की बाजार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक कच्चे कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। सरकार ने यह कदम कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चे माल कपास की बाजार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले का भाजपा सांसद एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने स्वागत किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से 18 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार कपास पर शुल्क छूट 19 अगस्त से प्रभावी होगी, जो 30 सितंबर तक लागू रहेगी। सरकार ने यह अनुमति कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार के लिए दी है। कपास पर अब तक 11 फीसदी आयात शुल्क के साथ-साथ कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर (एआईडीसी) भी लगता था। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "सरकार ने कपास पर आयात शुल्क को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। इससे देश के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से रॉ कॉटन सस्ती आने से हमारे कपड़े की उत्पादन लागत कम होगी और निर्यात बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ भारत का शेयर भी बढ़ेगा।" सरकार ने कपास आयात शुल्क में राहत ऐसे समय में दी है, जब कपड़ा क्षेत्र सहित भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में 50 फीसदी की भारी शुल्क दर का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी टैरिफ में मौजूदा 25 फीसदी शुल्क तथा अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क शामिल है, जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा। ये शुल्क भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद पर दंड के रूप में लगाया गया है।

केंद्र ने 6-लेन भुवनेश्वर बाईपास को दी मंजूरी

नई दिल्ली
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को ओडिशा में हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर 8307.74 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत से 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड (भुवनेश्वर बाईपास - 110.875 किमी) के निर्माण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। बड़ी आबादी वाले शहरों के कारण रामेश्वर से तांगी के बीच काफी भीड़भाड़ रहती है।

इससे निपटने के लिए 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड राजमार्ग के विकास का प्रस्ताव है।

उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रत्यक्ष तौर पर लगभग 74.43 लाख व्यक्ति-दिवस और अप्रत्यक्ष तौर पर 93.04 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित होगा। आसपास के क्षेत्रों में विकास, प्रगति और समृद्धि के नए रास्ते खोलेंगे। यह परियोजना 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच-55, एनएच-57 और एनएच-655) और एक राज्य राजमार्ग (एसएच-65) को जोड़ती है।

कोलकाता में शुरू होगा मेट्रो का नया अध्याय

कोलकाता
भारत की पहली मेट्रो सिटी कोलकाता अब सबसे तेजी से विस्तार पाता हुआ नेटवर्क बनने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पूजा से पहले कोलकातावासियों को 13.62 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन का तोहफा देंगे। मेट्रो रेलवे ने मंगलवार शाम बयान जारी कर बताया कि तीन अहम रूट- ग्रीन लाइन (एस्प्लेनेडझसीलदह), येलो लाइन (नॉआपाड़ाझजय हिंद विमानबंदर) और ऑरेंज लाइन (हेमंत मुखोपाध्यायझबेलियाघाटा) यात्रियों के लिए खोले जाएंगे। इससे हावड़ा मैदान से लेकर साल्ट लेट तक और दक्षिणेश्वर से लेकर दक्षिण कोलकाता के चप्पे-चप्पे तक महानगर कोलकाता मेट्रो से जुड़ जाएगा। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होना है। यह केवल बुनियादी ढांचे का विस्तार नहीं बल्कि कोलकाता की जीवनशैली में बड़ा बदलाव लाने वाली पहल मानी जा रही है। दशकों से यातायात जाम, भीड़भाड़ और खासकर दुर्गा पूजा के समय की अव्यवस्था झेलने वाले शहर के लिए यह नया नेटवर्क एक तरह का त्योहारी तोहफा साबित होगा।

केंद्र ने कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के विकास को दी मंजूरी

नई दिल्ली
केंद्र सरकार राजस्थान के कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का 1507 करोड़ की लागत से विकास करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज कोटा-बूंदी में हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने यहां पत्रकार वार्ता में बताया कि इस परियोजना में 20 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले एक टर्मिनल भवन का निर्माण शामिल है। व्यस्त समय में यह टर्मिनल भवन 1000 यात्रियों (पीएचपी) को संभालने में सक्षम होगा। इसकी वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) होगी। रनवे 11/29 का आकार 3200 मीटर गुना 45 मीटर होगा। ए-321 प्रकार के विमानों के लिए 07 पार्किंग बे के साथ एक एप्रन भी होगा। दो लिंक टैक्सीवे, एटीसी-सह-तकनीकी ब्लॉक, अग्निशमन केंद्र, कार पार्क और संबंधित कार्य परियोजना में शामिल हैं। मौजूदा कोटा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व में है। इसमें 1220 मीटर गुणा 38 मीटर आयाम का एक रनवे (08/26) शामिल है, जो कोड 'बी' विमानों (जैसे डीओ-228) के लिए उपयुक्त है और एक एप्रन है जो ऐसे दो विमानों को समायोजित कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि चंबल नदी के तट पर स्थित कोटा को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कोटा भारत के शैक्षिक कोचिंग केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। राजस्थान सरकार ने ए-321 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को लेकर एएआई को 440.06 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित की है। यह ओडिशा के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को निर्बाध कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। यह परियोजना कटक, भुवनेश्वर और खोरधा शहरों से भारी वाणिज्यिक यातायात को मोड़कर ओडिशा और अन्य पूर्वी राज्यों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगी। इससे माल ढुलाई की दक्षता बढ़ेगी, रसद लागत कम होगी और क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी। विकसित कॉरिडोर 10 आर्थिक केंद्रों, 4 सामाजिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़कर बहु-मॉडल एकीकरण को बढ़ाएगा।

राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की ओर से राष्ट्रपति और राज्यपालों के समक्ष विधेयकों को प्रस्तुत करने पर संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विकल्पों पर भेजे गए रेफरेंस पर आज से सुनवाई शुरू कर दी। उच्चतम न्यायालय ने आज अटार्नी जनरल से पूछा कि अगर राज्यपाल लंबे समय तक विधेयक को लंबित रखते हैं तो उस पर क्या होना चाहिए। संविधान बेंच कल यानी 20 अगस्त को भी सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखे जाने की वजह से उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय बेंच ने फैसला दिया होगा। कोर्ट ने अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी से पूछा कि अगर कोर्ट के सामने ऐसी याचिका आए जिसमें राज्यपाल बरसों तक विधेयक को लंबित रखे तो संवैधानिक रुप से क्या किया जा सकता है। कोर्ट ने पूछा कि उन लंबित विधेयकों पर सहमति मानने का कोर्ट का फैसला गलत है तो दूसरा विकल्प क्या है। तब अटार्नी जनरल ने कहा कि ऐसी विकट स्थिति में भी कोर्ट राज्यपाल का काम अपने हाथ में नहीं ले सकती और विधेयकों पर सहमति मानने का फैसला नहीं दे सकती है।

स्वदेशी माल बेचने के लिए व्यापारियों ने लगाएं बैनर

दिव्य दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन (फेस्टा) ने सदर बाजार के सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों पर बैनर लगाकर घोषणा करें कि उनकी दुकान में स्वदेशी सामान उपलब्ध है। इसी कड़ी में कई व्यापारी अपनी दुकानों पर बैनर और पोस्टर लगाना शुरू कर चुके हैं। फेस्टा के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा और अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया कि सैकड़ों व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर स्वदेशी माल बेचने की घोषणा की है। पम्मा ने कहा कि आने वाले त्योहारों में सदर बाजार में लगभग सभी दुकानों पर स्वदेशी माल ही बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के अनुसार दिवाली पर जीएसटी में बदलाव होने के बाद स्वदेशी माल कम दामों में उपलब्ध होगा और विदेशी माल का मुकाबला किया जा सकेगा। सदर बाजार में लगभग 40,000 दुकानें हैं और फेस्टा इस महीने के अंत तक सभी व्यापारियों तक यह अभियान पहुंचाने का प्रयास करेगा।

सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित

दिव्य दिल्ली : द्वारका सेक्टर-18 स्थित विजय वीर आवास में चरण जीत सिंह मजीठिया के सहयोग से पूर्व राज्यपाल और किसानों के हमदर्द चौधरी सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सभा में उपस्थित सदस्यों ने बताया कि चौधरी सत्यपाल मलिक हमेशा किसानों के हित में अग्रणी भूमिका निभाते रहे और राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए, जिनसे आज भी किसानों को लाभ मिलता है। श्रद्धांजलि सभा में पंचम मानव सेवा एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के मुखप्रबंधक चरण जीत सिंह मजीठिया के साथ मनोज कुमार, वेदपाल दलाल, मनु डाबश, नरेंद्र कुंडू, रणबीर मलिक, रणबीर गुलिया, रमेश टकसक, आजाद सिंह, जगदीश पहलवान, ओमप्रकाश गांदस, राकेश गुलिया, रामकवार अहलावत, भाई मनोज और दलवीर सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हवन का आयोजन भी किया गया, जिसमें राजेश हुड्डा सहित अन्य लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर चौधरी सत्यपाल मलिक के सामाजिक योगदान को याद किया। इस कार्यक्रम ने उनके उत्कृष्ट योगदान और समाज सेवा की भावना को पुनः सामने लाया।

'झूठ की दुकान और शोरूम' चला रहे राहुल गांधी: गौरव भाटिया

नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कथित वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। भाटिया ने कहा कि राहुल 'मोहब्बत की दुकान' नहीं बल्कि 'झूठ की दुकान और शोरूम' चला रहे हैं।भाजपा प्रवक्ता भाटिया ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित फजी मतदान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारे सामने ऐसी कोई ठोस सामग्री नहीं है जो बताती हो कि फजी मतदान हुआ था।" इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम सभी ने देखा है कि एक तरफ संविधान की, सत्य की और भारत की जनता की सच्चाई की ताकत है और दूसरी तरफ अराजकता और विध्वंस करने वाला राहुल गांधी का मॉडल, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाना और जब आरोप का प्रमाण मांगा जाए तो भाग जाना। वोट चोरी का आरोप तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं, ईवीएम खराब है, वीवी पैट से मिलान ठीक नहीं होता है। तो ये राहुल और विपक्ष सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।

लोकसभा की कार्यवाही अब 22 भाषाओं में उपलब्ध

नई दिल्ली
लोकसभा की कार्यवाही अब 22 भाषाओं में उपलब्ध होगी। अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन को इस भाषांतरण सुविधा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में भाषांतरण की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस सुविधा का लाभ उठायें। प्रारंभ होने पर आज अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को सूचित किया कि अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त, 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में भाषांतरण की सुविधा प्रदान की जा रही थी। इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से हम संविधान में उल्लिखित सभी 22 भाषाओं में भाषांतरण सुविधा उपलब्ध करा पा रहे हैं।

एससीओ शिखरवार्ता के लिए चीन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें तियानजिन में आयोजित हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश और निमंत्रण सौंपा। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और अपनी स्वीकृति व्यक्त की। साथ ही उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिंगपिंग के साथ वार्ता के इतर द्विपक्षीय वार्ता को लेकर उत्सुकता जाहिर की। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार वांग यी ने विदेश मंत्री डॉ एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक और विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक के बारे में अपना सकारात्मक मूल्यांकन भी साझा किया। इस बैठक की वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सह-अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री ने वांग यी के साथ हुई मुलाकात में सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर बल दिया और सीमा प्रश्न के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने पिछले वर्ष कजान में राष्ट्रपति शी के साथ अपनी बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर और सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया। यह प्रगति कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली सहित पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक हित और पारस्परिक संवेदनशीलता पर आधारित है।

उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन की चीनी अध्यक्षता के प्रति समर्थन व्यक्त किया और कहा कि वे तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन के बीच स्थिर, विश्वसनीय और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इससे पहले ने भारत-चीन के बीच 24वें विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने आज हैदराबाद हाउस में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों में अच्छे सुधार का रूख है तथा सीमा पर शांति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क में अच्छी प्रगति हो रही है।

वार्ता में अपने प्रारंभिक संबोधन में डोभाल ने कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिंगपिंग ने पिछले वर्ष अक्टूबर में कजान में परस्पर संबंधों के बारे में जो रूख तय किया था उस दिशा में काफी प्रगति हुई है। एक नया वातावरण तैयार हुआ है जिसके आधार पर आगे बढ़ने के लिए हम प्रयासरत है। चीन के विदेश मंत्री और सीमा संबंधी संवाद के विशेष प्रतिनिधि वांग यी ने भी डोभाल के के विचारों के कथन को दोहराते हुए कहा कि हमें खुशी है कि सीमा पर स्थायित्व बहाल हो गया है। द्विपक्षीय संबंधों में विगत वर्षों में हुए घटनाक्रम के संदर्भ में उन्होंने कहा कि आपसी टकराव हमारे हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास और जमीनी हकीकत से हमें यह संदेश मिलता है कि दोनो देशों के बीच स्वस्थ्य संबंध दोनों पक्षों के दीर्घकालीक हितों में है। मेहमान विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आगामी चीन यात्रा का हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संघठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेने के लिए चीन यात्रा पर जाने वाले हैं।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397